epaper.dehatsandesh.com

3 डीसी कठुआ ने आईसीडीएस व समाज कल्याण योजनाओं की समीक्षा की

5 टी 20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर बोले पैट कमिंस मेरे पास समय ही कम पड़ गया

8 अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक जल्दी तैयार होने वाला फल -पपीता

न्यूनतम 10 मौसम जम्मू अधिकतम 19

E-mail: dehatsandesh@gmail.com

देहात संदेश

जम्मू-कश्मीर का एकमात्र ग्रामीण दैनिक

वर्ष-23, जम्मू तवी, अंक-31 | जम्मू तवी, बुधवार 04 फरवरी, 2026 | मूल्य-3 रूपये- (लेह) 4 रूपये | पृष्ठ -8

मुझे विश्वास है कि शिक्षक और उनका कौशल समाज की रीढ़ और राष्ट्र की आत्मा हैं: उपराज्यपाल

जम्मू, 03 फ़रवरी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को दूरदर्शी शिक्षकों की आवश्यकता पर बल दिया जो छात्रों को भविष्य की अनिश्चितताओं, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के व्यवधान, जलवायु परिवर्तन, के लिए तैयार कर सकें, उन्हें नवाचारों में अग्रणी बनने के लिए प्रेरित कर सकें और एक गतिशील एवं नवाचार-संचालित अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर सकें।

उपराज्यपाल जम्मू के गांधी नगर स्थित पद्म श्री पद्म सचदेव सरकारी महिला महाविद्यालय में आयोजित प्रेरक शिक्षक पुरस्कार समारोह में बोल रहे थे। समारोह में जम्मू के विभिन्न विद्यालयों के कुल 101 सर्वश्रेष्ठ प्रेरक शिक्षकों को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने चरित्र निर्माण और प्रतिभाओं के विकास में शिक्षण समुदाय के बहुमूल्य योगदान की सराहना की जो भविष्य

को पूरी गति से नया रूप दे रहे हैं और युवा छात्रों को एक अनिश्चित दुनिया का सामना करने के लिए कौशल और साहस प्रदान कर रहे हैं। उपराज्यपाल ने कहा, मेरा मानना है कि शिक्षक और उनका कौशल समाज की रीढ़ और राष्ट्र की आत्मा हैं।

उपराज्यपाल ने कहा कि जिस प्रकार एक कुशल कारीगर भट्टी में काम करता है, उसी प्रकार शिक्षक भी जानते हैं कि सीखने की प्रेरणा जिज्ञासा से ही मिलती है। उन्होंने कहा, प्रेरक शिक्षक रटने से बचते हैं और विज्ञान को आकर्षक कहानियों में पिरोते हैं जो कक्षा को जीवंत बना देती हैं। उनके लिए इतिहास केवल तिथियों और समय-सीमाओं तक सीमित नहीं है बल्कि मानव विजय और पतन की जीवंत गाथाओं में तब्दील हो जाता है।

उपराज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि हमें और अधिक प्रेरक शिक्षकों की आवश्यकता है जो छात्रों को निष्क्रिय श्रोताओं से साहसी अन्वेषकों में बदल सकें। शिक्षक भविष्य की नींव हैं। कक्षा केवल चार दीवारें और एक काला बोर्ड नहीं है। कक्षा एक लोहार की धधकती भट्टी है जहाँ भविष्य को आकार दिया जाता है।

मैं ऐसी कक्षाओं की कल्पना करता हूँ जहाँ शिक्षक केवल किताबी उत्तर न दें बल्कि गहन प्रश्नों के माध्यम से जिज्ञासा को प्रेरित करें। उपराज्यपाल ने कहा, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और जीवंत समाज के निर्माण के लिए शिक्षार्थियों को सूचना के निष्क्रिय उपभोक्ताओं से बदलकर सूचना का गहन विश्लेषण करने वाले तीक्ष्ण विश्लेषकों में परिवर्तित करना आवश्यक है।

उपराज्यपाल ने शिक्षकों से अपनी कक्षाओं में सहयोग की संस्कृति विकसित करने का आग्रह किया।उन्होंने कहा , सच तो यह है कि आने वाली दुनिया उन्हीं की है जो टीम के रूप में काम करते हैं। इसलिए हमें कक्षाओं को सहयोग केंद्रों में बदलना होगा जहाँ शोध, लेखन और नवाचार सामूहिक प्रयासों के रूप में विकसित हों। उन्होंने शिक्षण समुदाय को पाठ्यक्रम के कठोर नक्शे से परे सोचने की सलाह दी।

नाबार्ड ने प्राथमिकता क्षेत्र के लिए 49,795.58 करोड़ की क्रेडिट क्षमता का अनुमान लगाया, मुख्य सचिव ने फोकस पेपर जारी किया

जम्मू, 03 फ़रवरी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने 2026-27 के लिए जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के तहत ?49,795.58 करोड़ की क्रेडिट क्षमता का अनुमान लगाया है। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आज नाबार्ड द्वारा आयोजित क्रेडिट सेमिनार के दौरान फोकस पेपर जारी किया। इस सेमिनार ने नीति निर्माताओं, बैंकरों और अन्य प्रमुख हितधारकों को क्षेत्र में स्थायी और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रणनीतियों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान किया। सभा को संबोधित करते हुए, मुख्य सचिव ने नाबार्ड द्वारा फोकस पेपर के लॉन्च पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने अंतिम मील क्रेडिट समावेशन- अछूतों तक पहुंच विषय पर जोर दिया, और पोटेंशियल लिंक्ड प्लान PLP को एक महत्वपूर्ण योजना उपकरण बताया जो क्रेडिट प्रवाह और विकास प्राथमिकताओं का

मार्गदर्शन करता है। उन्होंने कहा कि नाबार्ड के अनुमान यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य हैं, और समय पर और पर्याप्त क्रेडिट के साथ किसान क्रेडिट कार्ड के सार्वभौमिक कवरेज की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में आरआईडीएफ की भूमिका की सराहना की। निर्वाह खेती से व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य कृषि की ओर बदलाव पर जोर देते हुए, मुख्य सचिव ने बुनियादी ढांचे, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, सावधि ऋण, विशिष्ट फसलों और केसीसी में उपयुक्त बदलावों पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया, और औषधीय और सुगंधित पौधों को आय बढ़ाने के अवसरों के रूप में उजागर किया। मुख्य सचिव ने विश्वविद्यालयों, बैंकों और संबंधित विभागों को शामिल करते हुए एक एकीकृत दृष्टिकोण की वकालत की। उन्होंने ऊन प्रसंस्करण और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देने का आग्रह किया और क्रेडिट के माध्यम से स्वयं सहायता समूह और 卐लखपति दीदियों卐 को उभरते उद्यमियों के रूप में समर्थन देने पर जोर दिया। उन्होंने मिशन युवा की सफलता, संपार्श्विक के बजाय कौशल-आधारित ऋण की आवश्यकता, पर्यटन को विकेंद्रीकृत करने के लिए होमस्टे को बढ़ावा देने, हस्तशिल्प में प्रौद्योगिकी उन्नयन और पता लगाने की क्षमता पर भी प्रकाश डाला और स्ध्व को एक संभावित गेम चेंजर बताया जिसके लिए जम्मू-कश्मीर में केंद्रित रोलआउट की आवश्यकता है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक से संबद्ध बैंकिंग संवाददाताओं को माइक्रो एटीएम भी वितरित किए। फोकस पेपर में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, एमएसएमई,कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों के अलावा ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर देते हुए क्षेत्र-वार क्रेडिट अनुमानों की रूपरेखा दी गई है। कृषि क्रेडिट फ्लो को बढ़ाने, किसान उत्पादक संगठनों और ग्रामीण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मज़बूत करने, सेब और केसर जैसी बागवानी फसलों में उत्पादकता और क्षेत्र विस्तार में सुधार करने और वैल्यू एडिशन, संरचित मार्केटिंग सहायता और भौगोलिक संकेत पंजीकरण के माध्यम से हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया गया है।

पटवारी पर 17,000 रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में एसीबी ने एफआईआर दर्ज की

जम्मू, 03 फ़रवरी। भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) जम्मू ने उधमपुर के एक पटवारी के खिलाफ निर्माण कार्य की अनुमति देने के बदले कथित तौर पर 17,000 रुपये रिश्वत मांगने और लेने के आरोप में एफआईआर दर्ज की।

अधिकारियों ने बताया कि एक नागरिक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत जिसने सभी नियमों का पालन किया था के बाद एसीबी ने गोपनीय जांच की जिसमें रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई।

जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने एक लिखित शिकायत प्राप्त होने की जानकारी दी है जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि घर के निर्माण के लिए सभी नियमों/औपचारिकताओं का पालन करने के बावजूद, राजस्व विभाग के कर्मचारी मोहम्मद हनीफ, हलका पटवारी टिकरी ने अवैध रिश्वत की मांग शुरू कर दी। पहले उसने 30,000 और अंत में 17,000 रिश्वत पर समझौता किया, जिसके बदले में उसने निर्माण कार्य की अनुमति दी। साथ ही उसने शिकायतकर्ता को धमकी दी कि रिश्वत की राशि का भुगतान होने तक वह उन्हें लालटेन नहीं लगाने देगा।

बयान में कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए आरोपी अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए जम्मू में भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो से संपर्क किया है।

शिकायत प्राप्त होने पर एक गोपनीय जांच की गई जिससे आरोपी लोक सेवक द्वारा रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई। बयान में आगे कहा गया है, शिकायत प्राप्त होने पर गोपनीय जांच की गई जिससे आरोपी लोक सेवक द्वारा रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई। तदनुसार पुलिस स्टेशन एसीबी सेंट्रल जम्मू में केस एफआईआर संख्या 01/2026 धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दर्ज की गई और जांच शुरू की गई।

इसमें आगे कहा गया है कि जांच के दौरान एक टीम गठित की गई जिसने जाल बिछाया। आरोपी मोहम्मद हनीफ (पटवारी) ने गवाहों की उपस्थिति में शिकायतकर्ता से 17,000 रुपये की रिश्वत मांगी और स्वीकार की। बाद में, रिश्वत की राशि उसके कार्यालय से बरामद की गई और इसी बीच आरोपी पटवारी मौके से फरार हो गया। आरोपी की तलाश और जांच जारी है।

भारत-पाक मैचों को युद्ध की तरह कवर किया गया- उमर अब्दुल्ला ने खेलों के राजनीतिकरण की आलोचना की

जम्मू, 03 फ़रवरी। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप के हाई-प्रोफाइल मैच से हटने का पाकिस्तान का फैसला खेल और राजनीति के समस्याग्रस्त अंतर्संबंध का परिणाम था। क्रिकेट प्रेमी अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि खेल को राजनीतिक मुद्दों के साथ मिलाने से अक्सर प्रतिकूल परिणाम सामने आते हैं। मुख्यमंत्री ने यहां विधानसभा लॉन में संवाददाताओं से कहा कि हमने अब खेल और राजनीति के बीच अंतर करना पूरी तरह से बंद कर दिया है। मीडिया के माध्यम से बार-बार, जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होता है, इसे युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप इसे कभी भी सामान्य मैच की तरह कवर नहीं करते हैं। यह कहते हुए कि पाकिस्तान के साथ भारत के मैचों को हमेशा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है अब्दुल्ला ने कहा कि इस तरह के विवादों के पैदा होने का एक कारण यह भी है। जब हम दूसरे देशों के खिलाफ खेलते हैं, तो इस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन जब यह पाकिस्तान के खिलाफ होता है, तो इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है। तभी ऐसे हालात पैदा होते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए। हां, वे इस विश्व कप में भाग ले रहे हैं, लेकिन वे हमारे खिलाफ नहीं खेलेंगे।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर जन विश्वास अध्यादेश, 2025 पेश किया

जम्मू, 03 फ़रवरी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मूकश्मीर विधानसभा में जम्मू और कश्मीर जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अध्यादेश, 2025 (अध्यादेश संख्या 01 ऑफ 2025) पेश किया। यह अध्यादेश कुछ कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव करता है। इसका मकसद कई छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना और कई सेक्टरों में नियमों को आसान बनाना है। जम्मू में सिविल सचिवालय के कॉरिडोर में असेंबली हॉल के बाहर, प्रेस को बयान देते हुए, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को भारतीय सामानों पर आपसी टैरिफ कम करने के अमेरिकी सरकार के फैसले का स्वागत किया, और कहा कि इससे देश के कई निर्यातकों को राहत मिलेगी जो बढ़े हुए टैरिफ के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को घोषणा की कि भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं जिसके तहत वाशिंगटन भारतीय सामानों पर आपसी टैरिफ को मौजूदा 25

प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा। यह घोषणा भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका ने 27 अगस्त, 2025 से अमेरिकी बाजारों में आने वाले भारतीय सामानों पर 50 प्रतिशत का भारी टैरिफ लगाया था।ये टैरिफ हमारे लिए काफी बोझ साबित हो रहे थे, और हम यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये टैरिफ क्यों लगाए गए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका इस बात से खुश नहीं था कि हम रूस से तेल खरीदते हैं। मुख्यमंत्री ने यहां असेंबली के लॉन में पत्रकारों से कहा, ट्रंप ने घोषणा की है कि भारत सरकार ने अब रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है

जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा; विपक्षी सदस्यों ने जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग उठाई

जम्मू, 03 फ़रवरी। मंगलवार को जम्मूकश्मीर विधानसभा में हंगामेदार दृश्य देखने को मिले, जब विपक्षी बीजेपी सदस्यों ने जम्मू के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग उठाई, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने केंद्र शासित प्रदेश के बाहर कश्मीरियों के साथ कथित उत्पीड़न की घटनाओं पर ध्यान दिलाया। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने हंगामे के बावजूद प्रश्नकाल जारी रखा और देश के अन्य हिस्सों में कश्मीरियों के खिलाफ 卐हेट क्राइम卐 की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए पीडीपी विधायक वाहिद उर रहमान पारा द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया।जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, बीजेपी विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया ने जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्रों का मुद्दा उठाया, जो लॉ यूनिवर्सिटी की मांग के समर्थन में सड़कों पर हैं। उन्होंने कहा, 卐हम कश्मीर के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी देने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन क्षेत्र के छात्रों की मांग को पूरा करने के लिए जम्मू के लिए भी ऐसी ही एक यूनिवर्सिटी चाहते हैं।卐 जब सलाथिया बोल रहे थे, तो अन्य बीजेपी विधायक भी खड़े हो गए और मांग के समर्थन में तख्तियां दिखाईं और जम्मू के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे नारे भी लगाए।कांग्रेस विधायक निज़ाम-उद-दीन भट्ट ने तख्तियां दिखाने पर आपत्ति जताई और कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की हालिया बैठक में किसी भी मुद्दे को उठाते समय सदन की गरिमा बनाए रखने का फैसला किया गया था।

जम्मू में बांदीपोरा के लिए 50 बिस्तरों वाला क्रिटिकल केयर ब्लॉक, बाल चिकित्सा आईसीयू मंजूर

जम्मू, 03 फ़रवरी। जम्मू-कश्मीर सरकार ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) और संबद्ध योजनाओं के तहत बांदीपोरा जिले में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे को उन्नत किया जा रहा है। कांग्रेस विधायक निज़ाम-उद-दीन भट के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू ने कहा कि गंभीर देखभाल सेवाओं को मजबूत करने के लिए जिला अस्पताल बांदीपोरा में बड़े हस्तक्षेप चल रहे हैं। मंत्री ने कहा कि 100 बिस्तरों वाला जिला अस्पताल बांदीपोरा पहले से ही सीटी स्कैन, डायलिसिस यूनिट विशेष नवजात देखभाल इकाई (एसएनसीयू), ऑक्सीजन संयंत्र और वेंटिलेटर सहित सुविधाओं से सुसज्जित है। उन्होंने कहा कि आपातकालीन सीओवीआईडी रिस्पांस पैकेज- II (ईसीआरपी-II) के तहत अस्पताल में 12 बिस्तरों वाला बाल चिकित्सा हाइब्रिड आईसीयू, 30 बिस्तरों वाला ऑक्सीजन समर्थित बाल चिकित्सा वार्ड और 10 बिस्तरों वाला मातृ आईसीयू स्थापित किया गया है। पीएम-एभीएम के तहत बांदीपोरा के लिए 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक को मंजूरी दे दी गई है। तकनीकी बोली का मूल्यांकन किया गया और वित्तीय बोली खोली गई।

उन्होंने कहा कि एक जिला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला और 12 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों पर भी काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि ईसीआरपी-II के तहत जिले में चार छह बिस्तरों वाली और एक 20 बिस्तरों वाली प्रीफैब्रिकेटेड हेल्थकेयर इकाइयों की मंजूरी दी गई है। गुंड जहांगीर और ज़ुरिमांज़ में नए प्रकार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (एनटीपीएचसी) भवनों के पूरा होने में देरी पर मंत्री ने कहा कि देरी नाबार्ड से स्वास्थ्य सेवा विभाग कश्मीर को फंडिंग में बदलाव के कारण हुई, जो अब आवश्यक धनराशि जारी कर रहा है।

एयर-टू-एयर में मार करने वाली मिसाइल विकसित करने में डीआरडीओ को बड़ी सफलता

नई दिल्ली, 03 फ़रवरी। डीआरडीओ ने एक बड़ी तकनीकी सफलता हासिल की है। ओडिशा के तट के पास चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया गया। इस तकनीक की मदद से अब देश लंबी दूरी की एयर-टू-एयर में मार करने वाली मिसाइलें विकसित कर सकेगा, जिससे दुश्मनों पर रणनीतिक बढ़त मिलेगी। इस सफल परीक्षण के साथ भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास यह उन्नत तकनीक मौजूद है। डीआरडीओ के अनुसार, यह महत्वपूर्ण परीक्षण मंगलवार सुबह 10.45 बजे हुआ। परीक्षण के दौरान मिसाइल को पहले जमीन से लगाए गए बूस्टर की मदद से तेज रफ्तार दी गई। इसके बाद उसके सभी अहम हिस्सों ने बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक काम किया। इसमें बिना नोजल वाला बूस्टर, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट मोटर और फ्यूल फ्लो कंट्रोल सिस्टम शामिल थे। पूरी उड़ान के दौरान मिले आंकड़ों से यह साफ हुआ कि सिस्टम ने सही तरीके से काम किया। इस परीक्षण पर बंगाल की खाड़ी के किनारे तैनात कई आधुनिक उपकरणों से लगातार नजर रखी गई। इस लॉन्च को डीआरडीओ की अलग-अलग प्रयोगशालाओं के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने देखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता के लिए डीआरडीओ और इससे जुड़े उद्योगों की तारीफ की। वहीं, डीआरडीओ प्रमुख और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. समीर वी. कामत ने भी पूरी टीम को इस सफल उड़ान परीक्षण के लिए बधाई दी।

डोगरा समाज को पड़ोसी पहाड़ी-भाषी क्षेत्रों के साथ मिलकर अपनी सांस्कृतिक एकता को मज़बूत करना चाहिए : कर्ण सिंह

नई दिल्ली। डोगरा वेलफेयर एसोसिएशन, दिल्ली एनसीआर द्वारा राजेंद्र भवन में आयोजित वार्षिक मेल-मिलाप कार्यक्रम में डोगरी-पहाड़ी भाषा और संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और एकता का स्वर ज़ोरदार तरीके से गूंजा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जम्मू-कश्मीर के सदर-ए-रियासत यह चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. कर्ण सिंह ने कहा कि डोगरा समाज को कांगड़ा और चंबा जैसे पड़ोसी पहाड़ी-भाषी क्षेत्रों के साथ मिलकर अपनी सांस्कृतिक एकता को मज़बूत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुभाषिक होना समय की ज़रूरत है, लेकिन मातृभाषा की अनदेखी नहीं की जा सकती। यदि नई पीढ़ी को डोगरी बोलने के लिए प्रेरित नहीं किया गया तो यह भाषा आने वाले समय में संकट में पड़ सकती है। डॉ.सिंह ने भाषा संरक्षण में परिवारों, विशेष रूप से माताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए डोगरों से एकजुट, प्रगतिशील और दूरदर्शी बने रहने की अपील की। उन्होंने इस आयोजन के लिए सुदेश डोगरा और समस्त आयोजक टीम को

बधाई भी दी।

लोकप्रिय डोगरी-हिमाचली लोकगीत माये निं मेरिये, जम्मूऐ दी राहे, चंबा कितनी क दूर में कथित छेड़छाड़ के विरोध में प्रसिद्ध

गायक धीरज शर्मा ने गीत को उसके मूल शब्दों में प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति में ज्योति गुप्ता सहित अन्य कलाकारों ने भी भाग लिया।

(शेष पृष्ठ 8 पर)

साभार : अशोक कुमार मुनड़ेतिया

कृषि विज्ञान में कॅरियर की संभावनाएं

भारत विश्व के प्रमुख कृषि प्रधान देशों में से एक है और इसकी संपत्ति के सबसे बड़े स्रोतों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है- भूमि की पैदावार। देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 29.4 प्रतिशत है। इससे करीब 64 प्रतिशत सेवा क्षेत्र जुड़ा है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में वर्ष दर वर्ष कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है।

कृषि विज्ञान आधारित उच्च प्रौद्योगिकीय क्षेत्र है तथा इसमें रोजगार संभावनाएं हैं। पशु और पादप शोधकर्ता, खाद्य वैज्ञानिक, वस्तु ब्रोकर, पोषणविद, कृषि पत्रकार, बैंकर्स, बाजार विश्लेषक, बिक्री व्यावसायिक, खाद्य संसाधक, वन प्रबंधक, वन्यजीव विशेषज्ञ आदि के रूप में कृषि क्षेत्र में करियर बनाया जा सकता है।

कृषि अनुसंधान और शिक्षा कृषि विश्वविद्यालयों, संस्थानों तथा कृषि शिक्षा और पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालयों द्वारा संचालित की जाती है। कृषि विज्ञान के प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक विज्ञान भाग हैं, जिन्हें कृषि के व्यवहार तथा इसे समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस क्षेत्र में उत्पादन तकनीकें जैसे सिंचाई प्रबंधन, अनुशंसित नाइट्रोजन इनपुट्स गुणवत्ता और मात्रा की दृष्टि से कृषि उत्पादन में सुधार, प्राथमिक उत्पादों का अंतिम- उपभोक्ता उत्पादों में परिवर्तन, विपरीत पर्यावरणीय प्रभावों की रोकथाम तथा सुधार जैसे मिट्टी निम्नीकरण, कचरा प्रबंधन, जैव-पुनः उपचार सैद्धांतिक उत्पादन पारिस्थितिकी, फसल उत्पादन मॉडलिंग से संबंधित परंपरागत कृषि प्रणालियां, कई बार इसे जीविका कृषि भी कहा जाता है, जो विश्व के सर्वाधिक गरीब लोगों का भरण-पोषण करती है। ये परंपरागत पद्धतियां काफी रुचिकर हैं क्योंकि कई बार ये औद्योगिक कृषि की बजाय ज्यादा प्राकृतिक रिस्थितिकी व्यवस्था के साथ समाकलन का स्तर कायम रखती हैं जो कि कुछ आधुनिक कृषि प्रणालियों की अपेक्षा ज्यादा दीर्घकालिक होती हैं

न घबराएं ग्रुप इंटरव्यू से

सिंगल इंटरव्यू की बजाय आजकल कंपनियां ग्रुप इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट ज्यादा पसंद कर रही हैं। इसमें रिक्रूटिंग मैनेजर्स का बोर्ड कैंडिडेट का इंटरव्यू लेता है। अगर आप कुछ बातों का ख्याल रखें, तो इसे आसानी से क्लियर कर सकते है। नए फाइनैंशल ईयर में तमाम कंपनियां अपने रिक्रूटिंग प्रोसेस को फिर से शुरू करने की प्लानिंग कर रही हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों कुछ ऑर्गनाइजेशंस ने काफी संख्या में रिक्रूटमेंट करने के संकेत भी दिए थे। हालांकि अब कंपनियां वन बाई वन इंटरव्यू की बजाय ग्रुप इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रही हैं। इसके पीछे कंपनी के पास तमाम रीजन हैं। उनका मानना है कि इस तरह के इंटरव्यू में कम टाइम लगता है, क्योंकि एक कैंडिडेट को एक साथ तमाम लोग परखते हैं। अगर एक इंटरव्यूअर एक कैंडिडेट का इंटरव्यू करने में आधा घंटे का वक्त लगाता है, तो उनका ग्रुप कुछ मिनटों में ही कैंडिडेट की एबिलिटी जांच लेता है। इसके अलावा, मैनेजर्स के ग्रुप के पास कैंडिडेट के बारे में डिस्कस करने का भी ऑप्शन होता है, जबकि अकेले इंटरव्यूअर के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता।

करना होगा कुछ खास

बेशक, वन बाई वन इंटरव्यू और ग्रुप इंटरव्यू में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, बावजूद इसके कैंडिडेट्स को इस नए कॉन्सेप्ट के लिए कुछ खास तैयारियां करने की जरूरत होती है। एक्सपर्ट्स की अगर मानें, तो ग्रुप इंटरव्यू को बिजनेस मीटिंग की तरह ट्रीट करना चाहिए। आपको यह मानना चाहिए कि वहां इंटरव्यूअर आपके क्लाइंट हैं। बेशक, इस खास तरह के इंटरव्यू में आपका सामना न सिर्फ अलग-अलग तरह के लोगों से होगा, बल्कि वे आपसे असहमत भी हो सकते हैं। हालांकि अगर आप कुछ रूल्स को फॉलो करें, तो आप इसे क्लियर करके जॉब हासिल कर सकते हैं।

बैंकिंग सक्सेस के लिए जीके भी जरूरी

जीके या जनरल अवेयरनेस के बिना आप कोई भी कॉम्पिटीटिव एग्जाम पास करने की सोच भी नहीं सकते। बैंकिंग एग्जाम्स के लिए भी यही बात लागू होती है। जनरल अवेयरनेस के तहत इकॉनमी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स आदि सब्जेक्ट्स काफी अहमियत रखते हैं और एग्जाम्स में इनसे ही संबंधित नेशनल और इंटरनेशनल लेबल के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। दायरा बड़ा या यूं कहें कि अनलिमिटेड होने के कारण इस सब्जेक्ट की तैयारी करना हर किसी के लिए बड़ी चुनौती होती है। सवालों को लेकर कयास भी नहीं लगाए जा सकते हैं। कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। बैंक एग्जाम्स की बात करें तो इस सब्जेक्ट का फोकस उन टॉपिक्स पर ज्यादा होता है, जिनका बैंकिंग और इकॉनामी से वास्ता होता है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में काम करने वालों का इनसे ही वास्ता पड़ता है और एग्जाम में यही देखा जाता है कि इनमें स्टूडेंट्स की कितनी समझ है? वैसे तो इस सब्जेक्ट की तैयारी के बाद कोई यह नहीं कह सकता कि उसने सब कर लिया है, लेकिन अपने आप को देश-दुनिया की घटनाओं से अपडेट रख अपने लिए जमीन जरूर तैयार कर सकते हैं।

आपकी सफलता बहुत हद तक जनरल अवेयरनेस पर डिपेंड करती है। इसकी कई वजहें हैं। अव्वल तो यह कि हर एग्जाम में इसके अंक काफी होते हैं। दूसरा यह कि जनरल अवेयरनेस के सवालों को हल करने में बहुत ही कम समय लगता है। इसलिए आप इस सेक्शन में समय बचा कर अन्य सेक्शन में लगा सकते हैं। एग्जाम में भी इस सेक्शन को पहले करने की जरूरत होती है। जो लोग पहले दूसरे सेक्शन करते हैं, वे अक्सर समय न मिलने के कारण सवाल छूटने की शिकायत करते हैं। अन्य सेक्शन में अच्छा होने और अच्छा करने के बावजूद बहुतों के लिए एग्जाम में फेल होने का यह भी एक कॉमन रीजन है।

इकॉनामी और फाइनेंस

बैंकों के एग्जाम के लिए जनरल अवेयरनेस की तैयारी कर रहे हैं तो फोकस इकानॉमी और फाइनेंस पर ही रखें। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। वर्ल्ड बैंक और एडीबी से लेकर रिजर्व बैंक तक के बारे में। नामी कंपनियों और उनके प्रदर्शन से भी खुद को वाकिफ रखें। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले टर्म और शब्द संक्षेप पर भी पकड़ बनाएं। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और खेल की भी अच्छी तैयारी रखनी चाहिए।

रेग्युलर बनें

जनरल अवेयरनेस की तैयारी को काफी लोग हल्के में लेते हैं। लोग मान लेते हैं कि बैंक के लिए रीजनिंग और मैथ्स अहम है, जनरल अवेयरनेस नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है और यह भी नहीं है कि आप इस सब्जेक्ट की तैयारी थोड़े दिनों में कर सकते हैं। सबसे पहले तो जरूरत है चीजों को समझने की। अगर बैंकिंग और फाइनैंस के टर्म्स आप समझ जाएंगे तो बाद में आसानी से खुद को अपडेट रख सकते हैं। किसी अन्य चीज की तरह इस सब्जेक्ट में अच्छा करने के लिए भी नियमितता जरूरी है। करंट अफेयर्स से खुद को अपडेट रखने का रूटीन बनाएं इसलिए तैयारी अडवांस में ही शुरू कर देनी चाहिए। ऐसा करते खुद और दूसरों में अंतर देख सकते हैं। खुद को अपडेट रखने के लिए सबसे पहले तो न्यूज पेपर्स का सहारा लें। इसके अलावा करंट अफेयर की एक दो अच्छी पत्रिका भी नियमित रूप से पढ़ें। जनरल अवेयरनेस के सवालों का जायजा आप पिछले एग्जाम्स के सवालों से ले सकते हैं। एक और बात भी ठीक तरह समझ लें कि जनरल अवेयरनेस की तैयारी के लिए आप किसी एक बुक के सहारे नहीं रह सकते हैं। बाजार में हर जरूरत के हिसाब से काफी पुस्तकें और मैगजींस आ रही हैं। आप उनमें से कुछेक के नियमित पाठक बन सकते हैं। इस क्रम में समाचार चैनलों और इंटरनेट का भी सहारा लिया जा सकता है। नेट पर भी अब हिंदी और इंग्लिश, दोनों भाषाओं के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में भी काफी कुछ उपलब्ध है।

जर्नलिज्म, बेस्ट कॅरियर

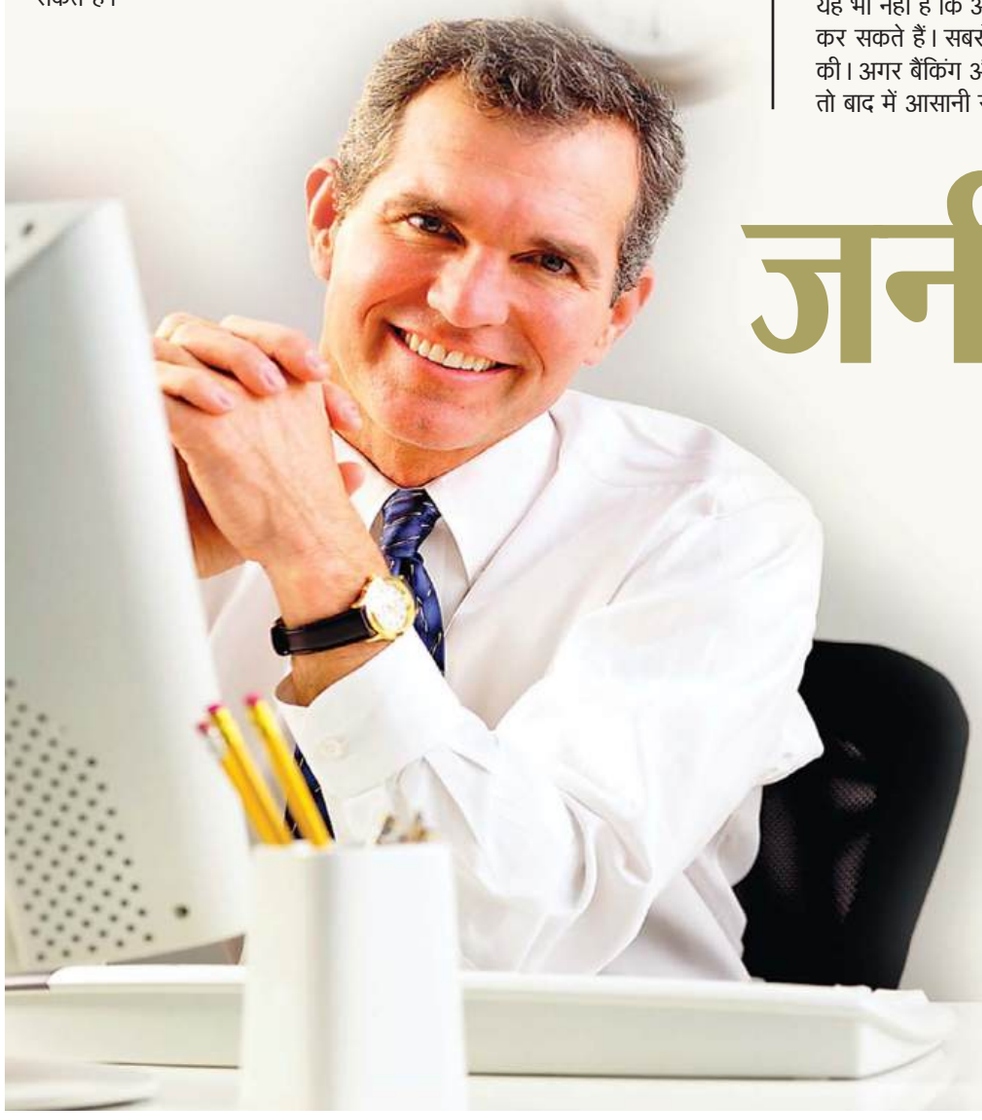

इन दिनों ज्यादातर युवाओं के लिए मीडिया आकर्षक कैरियर बनता जा रहा है। यदि लिखने-पढ़ने के शौकीन हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया है, तो मीडिया आपके लिए बेस्ट कैरियर साबित हो सकता है। दरअसल, आज मीडिया का काफी विस्तार हो चुका है। न केवल अखबार, टीवी और रेडियो, बल्कि इंटरनेट, मैग्जींस, फिल्म भी इसके विस्तारित क्षेत्र हैं। करेंट इवेंट्स, ट्रेंड्स संबंधित इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, एनालाइज करना आदि जर्नलिस्ट के मुख्य काम हैं।

ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करते हैं। इसमें रिटेन टेस्ट, इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन भी होता है। लिखित परीक्षा में स्टूडेंट्स के राइटिंग स्किल्स, जेनरल अवेयरनेस, एनालिटिकल एबिलिटी और एप्टीट्यूड की जांच की जाती है। एमसीआरसी के ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर ओबेद सिद्दीकी के अनुसार, एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोई विशेष तैयारी नहीं करनी होती है। टेस्ट के माध्यम से एप्लीकैंट के सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल इश्यू संबंधित ज्ञान को परखा जाता है।

करेंट अफेयर्स की जानकारी एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म के प्रोफेसर संपत कुमार कहते हैं कि जर्नलिज्म के लिए जरूरी तत्व है- करेंट न्यूज पर आपकी पकड़। ऐसे कैंडिडेट ही अच्छे जर्नलिस्ट बनते हैं, जिन्हें न्यूज की अच्छी समझ होती है और जिनकी राइटिंग स्किल बढ़िया होती है। साथ ही, उनका अपने पेशे के प्रति कमिटमेंट होना भी जरूरी है। दरअसल, किसी भी खबर का विश्लेषण कर उसे सरल रूप में पेश करना ही मास कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य होता है। यदि आप इस पेशे में सफल होना चाहते हैं, तो न्यूज पेपर्स, मैग्जींस और करेंट अफेयर्स संबंधित बुक्स जरूर पढ़ें।

इंटरव्यू है असली परीक्षा: दिल्ली यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में बैचलर करने के बाद मैं पीजी करना चाहता था। मैं प्रतिदिन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए दो लीडिंग न्यूजपेपर्स और कई मैग्जींस पढ़ा करता था। एंट्रेंस एग्जाम राइटिंग स्किल और सामयिक घटनाओं के प्रति आपकी जागरूकता की जांच के लिए किए जाते हैं। इसमें सफल होना आसान है। असली परीक्षा इंटरव्यूज के दौरान होती है। इस दौरान आपके न्यूज सेंस, कम्युनिकेशन स्किल और पेशेंस की भी जांच-परख होती है। यदि आप दब्बू किस्म के इंसान हैं या जल्दी अपना धैर्य खो देते हैं, तो आपको इस क्षेत्र में सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट नजरिया बनाना होगा कि आपका स्वभाव इस पेशे के अनुकूल है या नहीं।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक - नीलम सिंह गिल द्वारा देहात संदेश, गुरूद्वारा सुंदर सिंह रोड, जम्मू से प्रकाशित एवं नार्थलाईनस पबलिशर्स, 18-B, Phase- II, Industrial Estate, Gangyal, Jammu से मुद्रित। संपादक- नीलम सिंह गिल। फोन नंबरः- (95)191- 2574109 2548103 RNI Regd. No.: JKBIL/2004/13144 *Email: dehatsandesh@gmail.com, dehatsandesh@yahoo.com, dehatsandesh@rediffmail.com*

14वां पुलिस शहीद स्मारक नॉर्थ जोन टी-20 क्रिकेट चैंपियनशिप संपन्न, हरियाणा क्रिकेट अकादमी बनी विजेता

कठुआ, 03 फरवरी (हि.स.)। स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ में आयोजित 14वीं पुलिस शहीद स्मारक नॉर्थ जोन टी-20 क्रिकेट चैंपियनशिप का मंगलवार को भव्य समापन हुआ। फाइनल मुकाबले में हरियाणा क्रिकेट अकादमी ने शिवा क्रिकेट क्लब लुधियाना को 15 रनों से हराकर खिताब अपने नाम किया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि एडीजीपी मुख्यालय पीएचक्यू जम्मू एम के सिन्हा आईपीएस रहे। उन्होंने कठुआ पुलिस, शहीद वेलफेयर कमेटी और सभी प्रायोजकों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन न केवल शहीदों की स्मृति को जीवंत रखते हैं, बल्कि युवाओं में खेल भावना और अनुशासन को भी बढ़ावा देते हैं। उन्होंने विजेता व उपविजेता टीमों सहित आयोजन समिति के सदस्यों को ट्रॉफी, पदक और पुरस्कार वितरित किए। इसके अलावा उन्होंने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर उनके परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सम्मान स्वरूप उपहार भी प्रदान किए। इस अवसर पर एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा ने मुख्य अतिथि एडीजीपी एम. के. सिन्हा एवं विशिष्ट अतिथि डीआईजी जेकेएस रेंज जम्मू शिव कुमार शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, प्रायोजकों और गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने टूर्नामेंट की संक्षिप्त जानकारी देते हुए वर्ष 2025-26 के दौरान जिला पुलिस कठुआ द्वारा किए गए खेलकूद और अन्य गतिविधियों पर प्रकाश डाला।

डीसी कठुआ ने आईसीडीएस व समाज कल्याण योजनाओं की समीक्षा की

कठुआ, 03 फरवरी। उपायुक्त कठुआ राजेश शर्मा ने बुधवार डीसी कार्यालय परिसर में आयोजित बैठक में आईसीडीएस और समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक में एडीडीसी, आईसीडीएस व सोशल वेलफेयर विभाग के अधिकारी तथा फील्ड फंक्शनरी मौजूद रहे।

बैठक में बताया गया कि जिले में 1641 आंगनवाड़ी केंद्र कार्यरत हैं और पीएमएमवीवाई के तहत 3915 लाभार्थी पंजीकृत किए गए हैं। डीसी ने सभी योजनाओं की शत-प्रतिशत सैचुरेशन पर जोर देते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा और आईसीडीएस विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने एनएसएपी, आईएसएसएस, एसएमएएस, एडीआईपी सहित अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की और लाभार्थियों तक समयबद्ध, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से लाभ पहुंचाने पर बल दिया।

विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर पर्यावरण विज्ञान विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

जम्मू, 03 फ़रवरी (हि.स.)। विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर पर्यावरण विज्ञान विभाग द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य छात्रों को आर्द्रभूमियों के महत्व और पर्यावरणीय सततता में उनकी भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाना था।

इस अवसर पर प्रो. (डॉ.) रोमेश कुमार गुप्ता ने आर्द्रभूमियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ये जैव विविधता संरक्षण, जल विनियमन, बाढ़ नियंत्रण और जलवायु संतुलन में अहम भूमिका निभाती हैं। उन्होंने आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया।

कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने सक्रिय भागीदारी करते हुए चर्चाओं में हिस्सा लिया और आर्द्रभूमि संरक्षण से जुड़े विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

कार्यक्रम का संचालन प्रो. पूनम कुंदन, सहायक प्राध्यापक, पर्यावरण विज्ञान विभाग द्वारा किया गया। पूरे कार्यक्रम की निगरानी विभागाध्यक्ष डॉ. नेहा शर्मा ने की, जिन्होंने गतिविधि का मार्गदर्शन और समन्वय कर इसे सफल बनाया। इस अवसर पर सहायक प्राध्यापक प्रो. मुज़फ्फर शेख ने भी अपने विचार साझा किए और छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रेरित किया। कार्यक्रम का समापन वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए आर्द्रभूमियों के संरक्षण, जागरूकता और सतत उपयोग के संदेश के साथ किया गया।

बारामूला के उपायुक्त ने हज यात्रियों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम 2026 का उद्घाटन किया

बारामूला, 03 फ़रवरी (हि.स.)। बारामूला के उपायुक्त मिंगा शेरपा ने आज सरकारी मेडिकल कॉलेज बारामूला के संबद्ध अस्पताल में आयोजित हज यात्रियों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम 2026 का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर, उपायुक्त ने तीर्थयात्रियों के सुचारू और समय पर टीकाकरण को सुनिश्चित करने के लिए टीकाकरण केंद्र पर की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

इस कार्यक्रम में जीएमसी बारामूला के प्रधानाध्यापक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बारामूल, जिला टीकाकरण अधिकारी, चिकित्सा अधीक्षक; और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

इस पहल का उद्देश्य निर्धारित स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार हज यात्रियों के समय पर टीकाकरण और व्यापक स्वास्थ्य तैयारियों को सुनिश्चित करना है, जिससे एक सुरक्षित तीर्थयात्रा सुगम हो सके।

कृषि निदेशक ने विभाग की प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

जम्मू, 03 फ़रवरी (हि.स.)। जम्मू के कृषि निदेशक अनिल गुप्ता ने आज कृषि भवन के सम्मेलन कक्ष में जम्मू मंडल में चल रही प्रमुख कृषि पहलों की भौतिक और वित्तीय प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में समग्र कृषि विकास कार्यक्रम , केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस), पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) कार्यों, नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं और विभिन्न पोर्टलों पर सूचना अपलोड करने की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक के दौरान, एचएडीपी, सीएसएस, कैपेक्स और नाबार्ड योजनाओं के तहत स्वीकृत लक्ष्यों के मुकाबले प्रदर्शन के साथ-साथ योजना-वार और घटक-वार भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। निदेशक ने पारदर्शिता, जवाबदेही और निर्धारित दिशानिर्देशों के कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, कृषि समुदाय को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए आवंटित संसाधनों के त्वरित और विवेकपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। आरकेवीवाई और कृषि यंत्रीकरण घटकों पर विशेष जोर देते हुए, अनिल गुप्ता ने अधिकारियों को सिंचाई, कृषि उत्पादकता और यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए इन क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। मुख्य कृषि अधिकारियों को एचएडीपी परियोजनाओं की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि सभी घटकों के तहत व्यय निर्धारित समय सीमा के भीतर 100 प्रतिशत तक पूरा हो जाए।

सांसद मियां अल्ताफ अहमद ने आगामी जम्मू-राजौरी रेलवे लाइन परियोजना की घोषणा का किया स्वागत

जम्मू, 03 फ़रवरी (हि.स.)। अनंतनाग-राजौरी क्षेत्र के सांसद मियां अल्ताफ अहमद ने आज केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा आगामी जम्मू-राजौरी रेलवे लाइन परियोजना की घोषणा का स्वागत किया। एक बयान जारी कर सांसद मियां अल्ताफ ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा जम्मू-राजौरी रेलवे परियोजना की घोषणा का स्वागत किया। रेल मंत्री के अनुसार जम्मू-राजौरी रेल लाइन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का कार्य तेजी से प्रगति कर रहा है। मियां अल्ताफ ने कहा कि पिछले दो वर्षों से इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया था और केंद्रीय रेल मंत्री के साथ कई बार बैठक के दौरान इस पर चर्चा हुई थी जिन्होंने इस महत्वपूर्ण रेलवे लाइन की प्रगति और विकास का आश्वासन दिया था

केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू में 'साइबर शील्ड' राष्ट्रीय कार्यशाला-सह-जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ

जम्मू, 03 फ़रवरी (हि.स.)। केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू के कंप्यूटर साइंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय कार्यशाला-सह-जागरूकता कार्यक्रम साइबर शील्ड : डिफेंडिंग द डिजिटल फुटप्रिंट का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. संजीव जैन के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा, डिजिटल जिम्मेदारी और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रो. यशवंत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

अपने संबोधन में उन्होंने डिजिटल दुनिया में सतर्क और जिम्मेदार रहने की आवश्यकता पर बल देते हुए छात्रों व आम नागरिकों के बीच साइबर सुरक्षा जागरूकता को समय की मांग बताया। उन्होंने इस महत्वपूर्ण और प्रासंगिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए विभाग के प्रयासों की सराहना की।

कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष प्रो. दिनेश कुमार ने स्वागत एवं उद्देश्यात्मक वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए प्रतिभागियों को कार्यशाला के लक्ष्यों से अवगत कराया। उन्होंने मजबूत पासवर्ड के उपयोग, व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा, संदिग्ध लिंक से सावधानी और जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार जैसे व्यावहारिक साइबर सुरक्षा उपायों पर भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर प्रो. यशवंत सिंह द्वारा विभाग के फैकल्टी सदस्यों के साथ 'साइबर कवच' पुस्तिका का विमोचन किया गया, जिसमें सुरक्षित डिजिटल सहभागिता के लिए आवश्यक साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश और सर्वोत्तम अभ्यास शामिल हैं। माननीय कुलपति प्रो. संजीव जैन ने कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए विभाग की पहल की प्रशंसा की। यह राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान के सहयोग से आयोजित किया गया।

ट्री ऑफ लाइफ थीम पर क्षेत्रीय पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन

जम्मू, 03 फ़रवरी (हि.स.)। इंटेक जम्मू चैप्टर ने सैनिक स्कूल नगरोटा के सहयोग से 'ट्री ऑफ लाइफ' विषय पर एक क्षेत्रीय पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के 70 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। इनमें सैनिक स्कूल नगरोटा के 20 कैडेट्स के साथ-साथ एपीएस नगरोटा, एपीएस मीरां साहिब, एपीएस अखनूर, सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगरोटा और सेंट जोसेफ स्कूल नगरोटा के 10-10 छात्र शामिल रहे। प्रतिभागियों ने अपने पोस्टरों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, विरासत और जीवन की आपसी जुड़ाव जैसी थीम को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। छात्रों की कलाकृतियों में गहरी सोच, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और रचनात्मकता साफ झलकती रही। कार्यक्रम में इंटेक जम्मू-कश्मीर के संयोजक सलीम बेग सहित कई प्रतिष्ठित संरक्षण विशेषज्ञ और सेवानिवृत्त अधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने विद्यार्थियों से संवाद कर उनका मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर सैनिक स्कूल नगरोटा के प्राचार्य कैप्टन (आईएन) शिबू देवासिया ने प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं को जम्मू की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को समझने व संरक्षित करने के लिए प्रेरित करते हैं।

जम्मू के एमए स्टेडियम में गणतंत्र दिवस-2026 में भाग लेने वाली टीमों को राज्य कर विभाग ने किया सम्मानित

जम्मू, 03 फ़रवरी (हि.स.)। जम्मू और कश्मीर राज्य कर विभाग (एसटीडी) ने आज यहां एमए स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस-2026 समारोह में भाग लेने वाली विभागीय टीमों को सम्मानित करने के लिए एक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया। अभिनंदन समारोह का नेतृत्व राज्य कर आयुक्त पी.के. भट ने किया। जीएसटी सुधारों पर आधारित झांकी में योगदान और गणतंत्र दिवस परेड के दौरान मार्च पास्ट में भाग लेने के लिए टीमों को सम्मानित किया गया।

झांकी ने जीएसटी सुधारों के प्रमुख उद्देश्यों और उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया, जिसमें पारदर्शिता, अनुपालन में आसानी और करदाता-केंद्रित शासन पर विभाग के फोकस को उजागर किया गया।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रवर्तन और प्रशासन), जम्मू, नम्रिता डोगरा; अतिरिक्त आयुक्त (कर योजना, नीति और अग्रिम निर्णय), किशोरी लाल शर्मा; प्रधान उत्पाद शुल्क और कराधान प्रशिक्षण संस्थान, नग्रोटा, रेणु बाला; उपायुक्त (मुख्यालय) आशिमा शेर; उपायुक्त प्रवर्तन (केंद्रीय) सोनू परगल; डीसी अपील-I प्रदीप सिंह चिब; डीसी अपील-II कुलराज सिंह; सहायक आयुक्त (प्रवर्तन) सामिया शरीफ खान और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

सभा को संबोधित करते हुए राज्य कर आयुक्त पी.के. भट ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह में हमारी टीमों की भागीदारी विभाग की सामूहिक प्रतिबद्धता और व्यावसायिकता को दर्शाती है। उन्होंने आगे कहा कि जीएसटी झांकी जनता को सुधारों और उनके लाभों से अवगत कराने का एक महत्वपूर्ण माध्यम थी। तैयारियों में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, एमए स्टेडियम में सफल प्रस्तुति हमारी टीमों के निरंतर समन्वय, अनुशासन और कड़ी मेहनत का परिणाम थी।

इस तरह की पहल जन जागरूकता बढ़ाती है और विभाग की सुधारवादी छवि को मजबूत करती है। इस अवसर पर झांकी और मार्च पास्ट की योजना, डिजाइन, समन्वय और निष्पादन में योगदान देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह और प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए।

भाजपा जम्मू दक्षिण जिला महिला मोर्चा ने परिचयात्मक-सह-मासिक बैठक का किया आयोजन

जम्मू, 03 फ़रवरी (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी जम्मू दक्षिण जिला महिला मोर्चा ने आज त्रिकुटा नगर स्थित पार्टी मुख्यालय में एक परिचयात्मक-सह-मासिक बैठक और अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया।

इसका उद्देश्य संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करना तथा जिला स्तर पर समन्वय बढ़ाना था। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष अधिवक्ता नेहा महाजन ने की।कार्यक्रम में भाजपा जम्मू दक्षिण के जिला अध्यक्ष नरेश सिंह जसरोतिया और भाजपा महिला मोर्चा जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की महासचिव और संसदीय क्षेत्र प्रभारी इंजीनियर उर्वशी गुप्ता उपस्थित थीं।

बैठक का आयोजन जम्मू दक्षिण जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष मीतू शर्मा के नेतृत्व में किया गया।

कार्यक्रम के दौरान नव नियुक्त जिला प्रभारी श्रीमती सोनिया ठाकुर और सह-प्रभारी गुरमीत कौर को वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा उनकी जिम्मेदारियों और संगठनात्मक प्रतिबद्धता को मान्यता देते हुए औपचारिक रूप से सम्मानित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए अधिवक्ता नेहा महाजन ने बूथ स्तर पर लामबंदी और संगठनात्मक विस्तार में महिला मोर्चा की निर्णायक भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने सदस्यों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिला-केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने और मातृशक्ति के साथ पार्टी के जुड़ाव को मजबूत करने का आग्रह किया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के महत्व पर जोर दिया।

5 दिवसीय सिविल डिफेंस बेसिक ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू

जम्मू, 03 फ़रवरी (हि.स.)। एमआईईटी कॉलेज, कोट भलवाल जम्मू में सिविल डिफेंस का पांच दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस, जम्मू की देखरेख में तथा एमआईईटी कॉलेज के एनएसएस/एनसीसी कन्वीनर डॉ. प्रवीन कुमार के समन्वय से आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर में कॉलेज के 120 छात्र एवं स्टाफ सदस्य भाग ले रहे हैं। इस प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को प्राथमिक उपचार, आग से बचाव, अग्निशमन की तकनीक, सर्पदंश, चोकिंग जैसी आपात स्थितियों के प्रबंधन के साथ-साथ अन्य जीवन रक्षक उपायों की जानकारी दी जा रही है। विशेष रूप से हवाई हमलों, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के दौरान अपनाए जाने वाले निवारक उपायों पर जोर दिया जा रहा है। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर एमआईईटी कॉलेज के निदेशक डॉ. अंकुर गुप्ता ने सिविल डिफेंस टीम का स्वागत करते हुए इस तरह के उपयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सिविल डिफेंस जम्मू के चीफ वार्डन परमजीत कुमार ने व्याख्यान देते हुए पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा बताई और छात्रों को सिविल डिफेंस की भूमिका से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि सिविल डिफेंस राष्ट्रीय आपदा तैयारी प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा, जान-माल के नुकसान को कम करना और आपात स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, सिविल डिफेंस जम्मू के डिप्टी चीफ वार्डन आर. विजय मगोतरा ने भी संबोधित करते हुए संगठन में सिविल डिफेंस वार्डनों की भूमिका और सेवाओं पर प्रकाश डाला।

उत्तर रेलवे

ई-निविदा सूचना

निविदा संख्याः- 227, 228 & 229-2025-26-ADEN-I-ASR दिनांक : 02.02.2026

वरिष्ठ मंडल अभियन्ता-तृतीय/फिरोजपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित ई-निविदाएं, अंतिम तिथि **23.02.2026 समय 15:00 बजे** तक **www.ireps.gov.in** पर आमंत्रित की जाती है। निविदाकर्ता अपने मूल/संशोधित निविदा बंद होने की तिथि तथा समय तक प्रस्तुत कर सकते है। मैन्युअल निविदा मान्य नहीं है और ऐसे किसी भी मैन्युअल प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठेकेदार निविदा प्रपत्र की लागत और बयाना राशि का भुगतान केवल **www.ireps.gov.in** पोर्टल पर उपलब्ध ऑन लाइन साधनों के माध्यम जैसे नेट बैंकिंग, डेविट कार्ड, व केडिट कार्ड आदि से भुगतान कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट, बैंकस चेक, एफ.डी.आर. व रसीदों आदि के माध्यम से भुगतान की अनुमति नही हैं।

निविदा प्रकार	निविदा अनुभाग	बोली प्रणाली
खुला	कार्य	एकल बोली प्रणाली
निविदा अपलोड करने की तिथि	बोली शुरू की तिथि	बोली समापन की तिथि तथा समय
30.01.2026 एवं 31.01.2026	09.02.2026	23.02.2026 15:00 बजे

क्र.	निविदा संख्या	निविदा का विवरण			
1	227-2025-26-ADEN-I-ASR	अमृतसर वर्कशॉप में क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत, नाली के ढक्कन की मरम्मत, लीक हो रही/टूटी हुई छत की चादर और नालियों की मरम्मत का काम कारण।			
		विज्ञापन मूल्य (रु.)	ब्याना राशि	ऑफर की वैधता	समापन की अवधि
		1,09,28,626.00	2,04,700.00	60 दिन	12 महीने
		सामान प्रकृति का कार्यः "ट्रैक निर्माण कार्य के अलावा कोई भी सिविल कार्य।"			
2	228-2025-26-ADEN-I-ASR	नॉर्दर्न रेलवे मैकेनिकल वर्कशॉप अमृतसर में सर्विस बिल्डिंग की ईंट का काम, प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, फॉल्स सीलिंग, एल्युमिनियम के दरवाजे, वॉटरप्रूफिंग, लकड़ी का काम, पानी की सप्लाई और सैनिटरी इंस्टॉलेशन, पेंटिंग की मरम्मत।			
		विज्ञापन मूल्य (रु.)	ब्याना राशि	ऑफर की वैधता	समापन की अवधि
		1,92,20,588.62	2,46,100.00	60 दिन	12 महीने
		सामान प्रकृति का कार्यः "ट्रैक निर्माण कार्य के अलावा कोई भी सिविल कार्य।"			
3	229-2025-26-ADEN-I-ASR	सहायक मंडल अभियंता – प्रथम अमृतसर के सेक्शन में अटारी में 15 बेड वाले पुरुष बैरक का प्रावधान।			
		विज्ञापन मूल्य (रु.)	ब्याना राशि	ऑफर की वैधता	समापन की अवधि
		84,50,589.30	1,69,000.00	60 दिन	12 महीने
		सामान प्रकृति का कार्यः "ट्रैक निर्माण कार्य के अलावा कोई भी सिविल कार्य।"			

नोट : 1. निविदा डालने से पहले, निविदाकर्ता निविदा के संबंध में जारी किए गए किसी भी शुद्धिपत्र की जॉच करेंगे।
2. हिन्दी में किसी भी त्रुटि हेतु अंग्रेजी वर्जन का अवलोकन करे, तथा अंग्रेजी वर्जन ही मान्य होगे।

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ 366/26

GOVERNMENT OF JAMMU AND KASHMIR
DIRECTORATE OF INDUSTRIES AND COMMERCE
(REGISTRAR OF SOCIETIES/FIRMS JAMMU)
1st Floor, Udyog Bhawan, Rail Head Complex, Jammu
Telefax-0191-2474085 | Email: dirjmu.ind@jk.gov.in

PUBLIC NOTICE

The following members have applied for registration of society namely, **"THE JAMMU VEGETABLE & FRUIT ASSOCIATION" SITUATED AT SHOP NO. 13, SABZI MANDI, NARWAL, JAMMU, J&K** in the Office of Registrar of Society under Society Registration Act, 1860. Objections if any, from individuals, Institutions, State or Semi-State Government organizations may kindly be communicated to the office of Registrar of Societies (Director, Industries and Commerce) 1st Floor, Jawahar Lal Nehru Udyog Bhawan, Rail Head Complex, Jammu by post or in person within ten (10) days from the date of publication of this notice in the newspaper.

S. No	Name with Parentage	Occupation	Designation in Society
1	S. Surinder Singh S/o Lt. Sh. Isher Singh R/o Veer Sainik colony H.no 76 Sec-D	Businessman	President
2	Vishal Kohli S/o Lt. Subash Chander R/o H.No. 5/7 Circular Road Near Baba Lalji Chowk, Jammu	Businessman	Vice President
3	Ankur Anand S/o Sh. Brij Mohan Anand R/o H.No. 1 Lane -4 Vikas Lane Talab Tillo, Jammu	Businessman	General Secretary
4	Rajinder Kumar Sharma S/o Dev Dutt Sharma R/o E P 3/35, Rajinder Bazar, Jammu	Businessman	Jr. Vice President
5	Tarsem Gupta S/o Lt. Sh. Om Parkash Gupta R/o H.No. 27, Praveen Colony, Trikuta Nagar, Jammu	Businessman	Treasurer
6	Anil Kumar S/o Mohan Lal R/o GTB Nagar, Channi Rama, Jammu	Businessman	Secretary
7	Ashok Kumar S/o lt. Sh. Jala Ram R/o Mohalla Mistian Narwal Bala, Jammu	Businessman	Media Secretary

DIP/J-11036/25
Dtd:3-2-2026

Sd/-
Joint Director (M&P),
Dte. of Industries and Commerce
Jammu

संपादकीय

शारीरिक रूप से दिव्यांगों के मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए

यह अत्यंत चिंताजनक है कि समय-समय पर जम्मू-कश्मीर में शासन करने वाली सरकारों के बड़े-बड़े दावों के बावजूद, केंद्र शासित प्रदेश में शारीरिक रूप से दिव्यांग समुदाय आज भी अपनी लंबित मांगों के कारण लगातार संकट से जूझ रहा है, जिससे इन लोगों का जीवन और अधिक कठिन व चुनौतीपूर्ण बन गया है।

इसी संदर्भ में, जम्मू-कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के बैनर तले दिव्यांग व्यक्तियों के समुदाय ने सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय सहायता और कानूनी संरक्षण से जुड़ी अपनी लंबे समय से लंबित मांगों की पूर्ति के लिए प्रदर्शन किया है। मौजूदा सरकार को इन मांगों पर अत्यंत गंभीरता से विचार करना चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि समाज के इस वर्ग की जायज मांगों को बिना किसी देरी या भेदभाव के पूरा किया जा सके।

इस समुदाय की सबसे प्रमुख मांग पेंशन में वृद्धि की है, जो पूरी तरह से जायज है, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार उन्हें मात्र 1250 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है। यह राशि इतनी नगण्य है कि इससे एक व्यक्ति अपने एक महीने के ईंधन और बिजली के खर्च तक नहीं उठा सकता, जबकि दवाइयों, राशन, परिवहन, सब्जियों, फलों और अन्य दैनिक आवश्यकताओं का खर्च तो अलग ही है।

निस्संदेह, इस मुद्दे को बिना किसी और देरी के सरकार द्वारा उठाया जाना चाहिए ताकि समाज के इस कमजोर वर्ग को न्याय मिल सके और वे सम्मान व गरिमा के साथ जीवन जी सकें। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस समुदाय को लंबे समय से मुफ्त बिजली और पानी जैसी सुविधाओं से भी वंचित रखा गया है। उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने चाहिए ताकि इन लोगों को ये बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें, क्योंकि यह महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा देने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

कुल मिलाकर, सरकार को इन मांगों को एक विशेष मामले के रूप में लेते हुए बिना किसी बहाने या टालमटोल के पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह न्यायसंगत और वैध हैं। इसके अतिरिक्त, जम्मू-कश्मीर सरकार को पश्चिमी देशों से सीख लेते हुए ऐसा सार्वजनिक बुनियादी ढांचा विकसित करना चाहिए, जिसमें विशेष प्रावधान हों, ताकि दिव्यांग व्यक्ति बिना किसी सहायता के स्वतंत्र जीवन जी सकें।

फुटपाथों का निर्माण इस प्रकार होना चाहिए कि स्वचालित व्हीलचेयर पर चलने वाले लोग बिना किसी बाधा के उन पर चल सकें। शॉपिंग मॉल और छोटी दुकानों को भी इस पहलू पर ध्यान देना चाहिए ताकि वे व्हीलचेयर उपयोग करने वाले लोगों का स्वागत कर सकें। सभी सार्वजनिक शौचालय परिसरों और रेस्तरां व अन्य सार्वजनिक स्थानों के शौचालयों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अलग से सुविधाजनक व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वे स्वतंत्र और तनावमुक्त रह सकें।

लो-फ्लोर बसों की अवधारणा भी जम्मू-कश्मीर में सही ढंग से लागू नहीं की जा रही है, जो इस समुदाय के प्रति सरकार के उदासीन रवैये को दर्शाती है। इन सभी मुद्दों और इससे जुड़े अन्य पहलुओं पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, ताकि जम्मू-कश्मीर को दिव्यांग समुदाय के लिए एक बेहतर और समावेशी स्थान बनाया जा सके, क्योंकि यह शासन चलाने वालों की सामूहिक जिम्मेदारी है।

शैक्षणिक परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव का बजट

डॉ. अवधेश कुमार यादव

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत 2026-27 के संघीय बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल 1,39,289.48 करोड़ का अनुमानित प्रावधान किया गया है, जो विकसित भारत-2047 की मजबूत नींव रखने वाला कदम माना जा रहा है। यह राशि कुल बजट व्यय का लगभग 2.6 प्रतिशत है, जो पिछले वर्ष के बजट अनुमान से 8.27 प्रतिशत अधिक है तथा शिक्षा मंत्रालय के लिए अब तक का सर्वाधिक आवंटन है। हालांकि, यह धनराशि एनईपी-राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य (शिक्षा पर जीडीपी का 6 प्रतिशत व्यय) से काफी कम है लेकिन वृद्धि मुद्रास्फीति से ऊपर होने के कारण एनईपी के क्रियान्वयन, विशेषकर अनुसंधान, नवाचार, स्किलिंग तथा शिक्षा-रोजगार संबंध स्थापित करने के क्षेत्रों में गति प्रदान करेगी।

इस कुल आवंटन को शिक्षा मंत्रालय के दो प्रमुख विभागों में विभाजित किया गया है। पहला- स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को 83,562.26 करोड़ (6.35 प्रतिशत की वृद्धि) और दूसरा- उच्च शिक्षा विभाग को 55,727.22 करोड़ (11.28 प्रतिशत की वृद्धि)। यह वृद्धि एनईपी के मूल सिद्धांतों- पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य तथा जवाबदेही को सशक्त बनाती है, जहां शिक्षा को बहु-विषयी, लचीली, कौशल-आधारित और समावेशी बनाने पर बल दिया गया है।

स्कूल शिक्षा में अब तक का सर्वोच्च आवंटन एनईपी के प्रारंभिक से माध्यमिक स्तर तक की एकीकृत शिक्षा को मजबूत करता है। समग्र शिक्षा अभियान को 42,100 करोड़ प्राप्त हुए हैं, जो पूर्व-प्राथमिक से कक्षा 12 तक निरंतर शिक्षा, बुनियादी ढांचा विकास, शिक्षक प्रशिक्षण तथा डिजिटल क्लास रूम पर केंद्रित है। पीएम पोषण योजना को 12,750 करोड़ मिले हैं, जो 11 करोड़ से अधिक बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर उपस्थिति बढ़ाती है और कुपोषण घटाती है, जो एनईपी के समग्र विकास लक्ष्य से संरेखित है। केंद्रीय विद्यालय संगठन को 10,129 करोड़ तथा नवोदय विद्यालय समिति को 6,025 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देते हैं।

नवाचार को स्कूल स्तर पर एकीकृत करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स को 3,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष के 500 करोड़ से उल्लेखनीय छह गुना वृद्धि है। ये लैब्स छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करती हैं तथा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) आधारित प्रोजेक्ट्स पर कार्य करती हैं, जिससे ड्रॉपआउट दर घटेगी और विज्ञान में रुचि बढ़ेगी। एनईपी के डिजिटल एवं क्रिएटिव शिक्षा फोकस को देखते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, मुंबई के सहयोग से 15,000 माध्यमिक स्कूलों तथा 500 कॉलेजों में एवीजीसी (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स) कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित की जाएंगी। यह 'ऑरेंज इकोनॉमी' को मजबूत करेगा तथा छात्रों को प्रारंभिक स्तर से अनुसंधान-आधारित क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में शामिल करेगा।

उच्च शिक्षा में एनईपी का बहु-विषयी तथा अनुसंधान-उन्मुख दृष्टिकोण प्रमुख है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों को 17,440 करोड़ तथा यूजीसी को 3,709 करोड़ प्राप्त हुए हैं। आईआईटी, एनआईटी तथा आईआईएम जैसे संस्थानों के लिए बढ़ा फंड एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर केंद्रित है, जिसमें एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 250 करोड़ तथा एआई इन एजुकेशन पहल के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है। यह उभरती तकनीकों के एकीकरण को मजबूत करेगा। पीएम रिसर्च फेलोशिप को 10,000 स्कॉलर्स तक विस्तारित किया गया है, जो युवा शोधकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। पीएम रिसर्च चेयर योजना के लिए 200 करोड़ तथा पीएम वन नेशन-वन सब्सक्रिप्शन योजना को 2,200 करोड़ मिले हैं, जो शोध पत्रों तथा जर्नल्स तक केंद्रीकृत पहुंच सुनिश्चित करेगी तथा वैश्विक स्तर के अनुसंधान को समर्थन देगी।

एनईपी में अनुसंधान एवं विकास पर जीडीपी का कम से कम 1 प्रतिशत व्यय तथा एनआरएफ (राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन) के माध्यम से मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देने का प्रावधान है। इस बजट में उच्च शिक्षा में अनुसंधान आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि से यह लक्ष्य निकट आता दिखता है। पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स की स्थापना (औद्योगिक गलियारों के निकट विश्वविद्यालय, रिसर्च संस्थान, स्किल सेंटर तथा आवासीय सुविधाओं के साथ) इंडस्ट्री-एकेडमिया लिंकेज को मजबूत करेगी, जहां संयुक्त प्रोजेक्ट्स जैसे एआई, बायोटेक्नोलॉजी तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर कार्य होगा। हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना (कैपिटल सपोर्ट से), एसटीईएम में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाएगी, जहां वर्तमान दर अपेक्षाकृत कम है तथा एनईपी की लैंगिक समानता तथा अनुसंधान में महिलाओं की भूमिका को सशक्त बनाएगी।

यह राशि कुल बजट व्यय का लगभग 2.6 प्रतिशत है, जो पिछले वर्ष के बजट अनुमान से 8.27 प्रतिशत अधिक है तथा शिक्षा मंत्रालय के लिए अब तक का सर्वाधिक आवंटन है। हालांकि, यह धनराशि एनईपी-राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य (शिक्षा पर जीडीपी का 6 प्रतिशत व्यय) से काफी कम है लेकिन वृद्धि मुद्रास्फीति से ऊपर होने के कारण एनईपी के क्रियान्वयन, विशेषकर अनुसंधान, नवाचार, स्किलिंग तथा शिक्षा-रोजगार संबंध स्थापित करने के क्षेत्रों में गति प्रदान करेगी।

नए संस्थानों में तीन नए एनआईपीईआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पूर्वी भारत में एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी का अपग्रेड एनईपी के बहु-विषयी तथा व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देंगे। एनआईपीईआर फार्मास्यूटिकल रिसर्च पर फोकस करेंगे, जो बायोफार्मा तथा ड्रग डिस्कवरी में भारत को वैश्विक नेता बनाने की दिशा में सहायक होंगे। 'एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज' की हाई-पावर्ड स्टैंडिंग कमिटी गठित होगी, जो शिक्षा को सेवाओं क्षेत्र 10 प्रतिशत वैश्विक हिस्सेदारी लक्ष्य तथा उभरती स्किल्स से जोड़ेगी तथा एआई के प्रभाव का मूल्यांकन करेगी।

अन्य क्षेत्रों में 100,000 एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स जोड़ना, तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, वेटरनरी शिक्षा के लिए सब्सिडी तथा खेलो इंडिया मिशन के तहत स्पोर्ट्स साइंस एनईपी के स्वास्थ्य, पर्यटन तथा खेल शिक्षा को मजबूत करेंगे, जहां अनुसंधान जैसे स्पोर्ट्स साइंस में बायोमैकेनिक्स तथा पोषण पर फोकस होगा। एम्स, नई दिल्ली को 5,500.92 करोड़ तथा एनआईएमएचएएनएस-2 की स्थापना मेन्टल हेल्थ रिसर्च को बढ़ावा देगी। यह बजट शिक्षा व्यवस्था के मौजूदा परिदृश्य को सकारात्मक रूप से बदलने वाला है क्योंकि यह एनईपी के विभिन्न स्तंभों- अनुसंधान एकीकरण, समावेशिता, कौशल विकास तथा रोजगार-उन्मुखीकरण को एक साथ मजबूत करता है।

यह बजट अनुसंधान एकीकरण, समावेशिता, कौशल विकास तथा रोजगार-उन्मुखीकरण के माध्यम से एनईपी के स्तंभों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अनुसंधान पर फोकस एनआरएफ, पीएम रिसर्च चेयर, वन नेशन-वन सब्सक्रिप्शन, एआई तथा क्रिएटिव स्किल्स एवीजीसी लैब्स तथा इंडस्ट्री-एकेडमिया लिंकेज यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स, स्टैंडिंग कमिटी भविष्योन्मुखी हैं। यदि क्रियान्वयन मजबूत हो, फंड का उपयोग समयबद्ध व प्रभावी हो तथा राज्य स्तर पर समन्वय बढ़े तो यह शैक्षणिक परिदृश्य में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।

लेखक, राजकीय महाविद्यालय, कुल्लू में पत्रकारिता एवं जनसंचार विषय के सहायक प्रोफेसर हैं।

अमेरिकी टैरिफ कटौती में भारत से ज्यादा अमेरिका का हित

-डॉ. मयंक चतुर्वेदी

अंतरराष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति में कई बार फैसले तत्काल फायदे से अधिक दूरगामी मजबूरियों का नतीजा होते हैं। अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर पारस्परिक टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करना भी ऐसा ही एक निर्णय है, जिसे सतही तौर पर भारत के पक्ष में बड़ी जीत माना जा रहा है, किंतु गहराई से देखने पर यह कदम अमेरिका के अपने घरेलू हितों, खासकर महंगाई से जूझते आम अमेरिकी उपभोक्ताओं को राहत देने की मजबूरी का परिणाम अधिक नजर आता है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में भारत का धैर्य, संतुलित कूटनीति और दीर्घकालिक सोच आखिरकार रंग लाती दिखाई दी है।

पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका ने टैरिफ को एक राजनीतिक और रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत चीन, वियतनाम, बांग्लादेश और यहां तक कि भारत जैसे मित्र देशों पर भी भारी शुल्क लगाए गए। उद्देश्य इसके पीछे जो दिखा, वह घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और आयात को महंगा कर अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण देना रहा लेकिन व्यवहार में इसका असर उल्टा पड़ा। ऊंचे टैरिफ का सीधा बोझ अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ा, महंगाई बढ़ी और सप्लाई चेन में अस्थिरता आई। आज जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था महंगाई के दबाव से कराह रही है, तब ट्रंप प्रशासन को यह समझमें आया कि टैरिफ की यह आक्रामक नीति लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है।

कहना होगा कि यहीं से भारत के प्रति अमेरिकी रुख में बदलाव होता हुआ दिखता है। भारतीय उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत करना आज भारत से अधिक अमेरिकी बाजार में कीमतों को काबू में रखने की एक व्यावहारिक कोशिश भी है। भारत से आने वाले टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो पार्ट्स, केमिकल और आईटी सेवाएं अमेरिकी उपभोक्ताओं और उद्योगों के लिए अहम हैं। इन पर ऊंचा शुल्क अमेरिकी कंपनियों की लागत बढ़ाता था, जिसका असर सीधे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर पड़ता था। ऐसे में टैरिफ कटौती अमेरिका के लिए अपनी ही अर्थव्यवस्था को राहत देने का रास्ता बन गई।

वैश्विक तुलना करें तो भारत की स्थिति अब कहीं अधिक मजबूत नजर आती है। नए टैरिफ ढांचे में भारत पर 18 प्रतिशत शुल्क है, जबकि इंडोनेशिया पर 19, वियतनाम और बांग्लादेश पर 20 और चीन पर 34 प्रतिशत टैरिफ लागू है। यह अंतर वैश्विक निर्यात प्रतिस्पर्धा में बड़ा बदलाव है। अमेरिकी आयातक स्वाभाविक रूप से कम शुल्क वाले देशों से खरीद बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इस दौड़ में भारत अब अपने एशियाई प्रतिद्वंद्वियों से आगे खड़ा दिखेगा। यह बढ़त भारत की मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात रणनीति के लिए बेहद अहम कही जा सकती है।

इस फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू ऊर्जा और भू-राजनीति से जुड़ा है। रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर भारत पर लगाया गया अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ हटाया जाना इस बात का संकेत है कि अमेरिका व्यापार नीति को रणनीतिक लक्ष्यों से जोड़कर देख रहा है। अमेरिका के लिए यह फैसला रूस पर दबाव बढ़ाने और अपने सहयोगियों को एकजुट रखने की रणनीति का हिस्सा है, जबकि भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता में रखते हुए संतुलित रुख अपनाया हुआ है।

यहां भारत का धैर्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। रूस-युक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने सस्ते रूसी तेल की खरीद बढ़ाई, क्योंकि उसकी ऊर्जा जरूरतें और घरेलू अर्थव्यवस्था इसकी मांग करती थीं। पश्चिमी देशों के कई दबाव आते रहे, बावजूद भारत ने स्पष्ट किया कि ऊर्जा संबंधी फैसले राष्ट्रीय हित और बाजार परिस्थितियों के आधार पर होंगे। यही धैर्य और आत्मविश्वास अंततः भारत के पक्ष में अब आता हुआ दिखता है। पहले भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) का मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) और अब अमेरिका का खुद यह स्वीकार करना कि टैरिफ नीति में लचीलापन जरूरी है, आज यह साबित करता है कि जल्दबाजी के बजाय भारत द्वारा संतुलित कूटनीति उसके पक्ष में कितनी प्रभावी रही है।

इस व्यापार समझौते का सीधा प्रतिबिंब भारतीय शेयर बाजार में देखने को मिला, जहां समझौते के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में ऐतिहासिक तेजी दर्ज की गई। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी जबरदस्त उछाल दिखा है। ऑटो, आईटी, फार्मा, बैंकिंग और मेटल जैसे सेक्टर्स में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। यह बाजार प्रतिक्रिया इस बात का संकेत है कि निवेशक इस फैसले को भारत की मध्यम अवधि की आर्थिक वृद्धि के लिए सकारात्मक मान रहे हैं।

एक्सिस सिक्योरिटीज जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट भी यही कहती है कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता चालू खाते के घाटे को कम करने, रुपये को स्थिर रखने और बाहरी झटकों के प्रति भारत की संवेदनशीलता घटाने में मदद करेगा। बेहतर बाजार पहुंच और टैरिफ में स्थिरता से निर्यात बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग में निवेश आएगा और एफडीआई को मजबूती मिलेगी। खासकर वे सेक्टर, जिनकी अमेरिकी बाजार में मजबूत मौजूदगी है, उन्हें दीर्घकालिक लाभ मिलने की संभावना है।

इसके साथ ही यहां जो अभी सिर्फ भारत के हित में निर्णय को मान रहे हैं, उन्हें समझना होगा कि ये निर्णय भारत से ज्यादा अमेरिका के अपने हित में है, क?योंकि अमेरिका इस समय महंगाई और आर्थिक दबाव से गुजर रहा है, उसमें सस्ते और भरोसेमंद आयात के लिए भारत एक बड़ा, स्थिर और भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता है। टैरिफ घटाकर अमेरिका ने अपने उपभोक्ताओं को राहत दी है, वो सप्लाई चेन को भी स्थिर करना चाह रहा है और चीन पर निर्भरता कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह रणनीतिक रूप से अमेरिका के लिए बेहद जरूरी है।

भारत के लिए यह फैसला किसी एकतरफा रियायत से अधिक उसकी लगातार बढ़ती वैश्विक भूमिका की स्वाभाविक परिणति है। 'मेड इन इंडिया', पीएलआई स्कीम, निर्यात बढ़ाने की नीति और बहुपक्षीय कूटनीति ने भारत को उस मुकाम पर पहुंचाया है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं उसके साथ साझेदारी को मजबूरी नहीं, अवसर के रूप में देख रही हैं।

ऐसे में कहना यही होगा कि अमेरिका द्वारा टैरिफ घटाने का निर्णय एक अच्छा और व्यावहारिक फैसला है, इसके माध?यम से अमेरिका अपने नागरिकों को महंगाई की आग से बचाने की कोशिश में सफल हो सकता है। भारत के लिए यह पूरी तरह हितकारी है। निश?चित ही ये निर्णय भारत के धैर्य, संतुलन और दीर्घकालिक सोच की जीत है। सच ही कहा गया है कि जब आप धैर्य बनाए रखते हैं तब उस स्थिति में अंततः समय अपना परिणाम धैर्यवान के पक्ष में ही देता है। फिलहाल अमेरिका-भारत टैरिफ प्रकरण में आज यही सच्चाई सामने खड़ी नजर आती है।

कैंसर मौन महामारी, जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव

- योगेश कुमार गोयल

लोगों को कैंसर होने के संभावित कारणों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 4 फरवरी को 'विश्व कैंसर दिवस' मनाया जाता है। दरअसल, आज भी लगभग सभी लोगों के लिए कैंसर ऐसा शब्द है, जिसे अपने किसी परिजन के लिए डॉक्टर के मुंह से सुनते ही परिवार के तमाम सदस्यों की सांसें गले में अटक जाती हैं और पैरों तले की जमीन खिसक जाती है।

ऐसे में परिजनों को परिवार के उस अभिन्न अंग को सदा के लिए खो देने का डर सताने लगता है। बढ़ते प्रदूषण तथा पोषक खानपान के अभाव में यह बीमारी महामारी के रूप में तेजी से फैल रही है। भारत में तो कैंसर के करीब दो तिहाई मामलों का बहुत देर से पता चलता है और कई बार तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि हमारे देश में पिछले बीस वर्षों के दौरान कैंसर मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है और कैंसर से मौतों का आंकड़ा साल-दर-साल निरंतर बढ़ रहा है। प्रतिवर्ष कैंसर पीड़ित लाखों मरीज मौत के मुंह में समा जाते हैं।

कुछ वर्ष पूर्व तक कैंसर को लाइलाज रोग माना जाता था लेकिन कुछ वर्षों में कैंसर के उपचार की दिशा में क्रांतिकारी खोजें हुई हैं। जिसका नतीजा है कि अगर समय रहते कैंसर की पहचान कर ली जाए तो उसका उपचार किया जाना काफी हद तक संभव हो जाता है। कैंसर के संबंध में यह समझ लेना बेहद जरूरी है कि यह बीमारी किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है किन्तु अगर इसका सही समय पर पता लग जाए तो लाइलाज मानी जाने वाली इस बीमारी का उपचार अब संभव है। यही वजह है कि देश में कैंसर के मामलों को कम करने के लिए कैंसर तथा उसके कारणों के प्रति लोगों को जागरूक किए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ताकि वे इस बीमारी, इसके लक्षणों और इसके भयावह खतरे के प्रति जागरूक रहें।

कैंसर से लड़ने का सबसे बेहतर और मजबूत तरीका यही है कि लोगों में इसके प्रति जागरूकता हो, जिसके चलते जल्द से जल्द इस बीमारी की पहचान हो सके और शुरूआती चरण में ही इसका इलाज संभव हो। यदि कैंसर का पता शीघ्र लगा लिया जाए तो उसके उपचार पर होने वाला खर्च काफी कम हो जाता है। यही वजह है कि जागरूकता के जरिये इस बीमारी को शुरूआती दौर में ही पहचान लेना बेहद जरूरी माना गया है क्योंकि ऐसे मरीजों के इलाज के बाद उनके स्वस्थ एवं सामान्य जीवन जीने की संभावनाएं काफी ज्यादा होती हैं।

हालांकि देश में कैंसर के इलाज की तमाम सुविधाओं के बावजूद अगर हम इस बीमारी पर लगाम लगाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो इसके पीछे इस बीमारी का इलाज महंगा होना सबसे बड़ी समस्या है। वैसे देश में जांच सुविधाओं का अभाव भी कैंसर के इलाज में बड़ी बाधा है, जो बहुत से मामलों में इस बीमारी के देर से पता चलने का एक अहम कारण होता है।

यह जानना भी बहुत जरूरी है कि 'कैंसर' आखिर है क्या? जब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कमजोर हो जाती है तो शरीर पर विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमला करना शुरू कर देती हैं। ऐसी परिस्थितियों में कई बार शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित होकर अपने आप तेजी से विकसित और विभाजित होने लगती हैं। कोशिकाओं के समूह की इस अनियंत्रित वृद्धि को ही कैंसर कहा जाता हैं। जब ये कोशिकाएं टिश्यू को प्रभावित करती हैं तो कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैलने लगता है और कैंसर की यह स्थिति बहुत घातक हो जाती है।

दुनिया भर में कैंसर से लड़ने और इसे हराने के लिए निरन्तर चिकित्सीय खोजें हो रही हैं और इन प्रयासों के चलते ही अब कैंसर का शुरूआती चरणों में तो सफल इलाज संभव भी है। अगर शरीर में कैंसर होने के कारणों की बात की जाए तो इसके कई तरह के कारण हो सकते हैं लेकिन अक्सर जो प्रमुख कारण माने जाते रहे हैं, उनमें मोटापा, शारीरिक सक्रियता का अभाव, व्यायाम न करना, ज्यादा मात्रा में अल्कोहल व नशीले पदार्थों का सेवन, पौष्टिक आहार की कमी इत्यादि इन कारणों में शामिल हो सकते हैं। कभी-कभार ऐसा भी होता है कि कैंसर के कोई भी लक्षण नजर नहीं आते किन्तु किसी अन्य बीमारी के इलाज के दौरान कोई जांच कराते वक्त अचानक पता चलता है कि मरीज को कैंसर है लेकिन फिर भी कई ऐसे लक्षण हैं, जिनके जरिये अधिकांश व्यक्ति कैंसर की शुरूआती स्टेज में ही पहचान कर सकते हैं।

कैंसर के लक्षणों में कुछ प्रमुख हैं- वजन का घटते जाना, शरीर में रक्त की कमी, निरन्तर बुखार बने रहना, शारीरिक थकान व कमजोरी, चक्कर आना, उल्टी होना, दौरे पड़ना, आवाज में बदलाव, सांस लेने में दिक्कत, खांसी के दौरान खून आना, लंबे समय तक कफ रहना और कफ के साथ म्यूकस आना, कुछ भी निगलने में दिक्कत होना, पेशाब और शौच के समय खून आना, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ या सूजन होना, माहवारी के दौरान अधिक स्राव होना इत्यादि।

कीमोथैरेपी, रेडिएशन थैरेपी, बायोलॉजिकल थैरेपी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इत्यादि के जरिये कैंसर का इलाज होता है किन्तु यह प्रायः इतना महंगा होता है कि एक गरीब व्यक्ति इतना खर्च उठाने में सक्षम नहीं होता। इसलिए जरूरत इस बात की महसूस की जाती रही है कि कैंसर के सभी मरीजों का इलाज सरकारी अस्पतालों में हो या निजी अस्पतालों में, सरकार ऐसे मरीजों के इलाज में यथासंभव आर्थिक सहयोग करे क्योंकि जिस तेजी से देश में कैंसर मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए केवल सरकारी अस्पतालों के भरोसे कैंसर मरीजों के इलाज की कल्पना बेमानी होगी। इसके अलावा सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि कैंसर को लेकर समाज में बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाएं जाएं।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

जिला कराटे में टीएसएच का दबदबा, 59 खिलाड़ियों ने जीते पदक

एजेंसी

कानपुर। बाल निकुंज, स्वरूपनगर में आयोजित आठवीं जिला कराटे चैंपियनशिप में टीएसएच (द स्पोर्ट्स हब) के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता पर वर्चस्व कायम किया। इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शहर के कुल 130 बच्चों ने भाग लिया। इसमें टीएसएच के 59 खिलाड़ी शामिल रहे। टीएसएच से प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों में 12 एकेडमी के बच्चे थे, जबकि शेष खिलाड़ी ईडब्ल्यूएस वर्ग से थे। प्रतियोगिता में टीएसएच के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए कुल 59 पदक अपने नाम किए। इनमें 32 स्वर्ण, 19 रजत और आठ कांस्य पदक शामिल हैं। प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले टीएसएच के खिलाड़ियों में मेहर भट्टर, अनन्या गुप्ता, रिधिमा सरावगी, हितिका काया, आयांश गुप्ता, हर्षिका वामन, रिद्धि बख्शी, काव्या सक्सेना, श्रृष्टि, आरुषि वर्मा, आराध्या राज, आदित्य कुमार, आरव कुमार, रोमन जायसवाल, रिदम सिंह, अभिनव मिश्रा, श्रेयांश गुप्ता, जुनैद रज़ा, आदर्श कुमार, अंशिका कुशवाहा, काइरा विश्वास, सगुन सिंह, वृद्धि द्विवेदी, कृतिका वर्मा, प्रज्ञा कुमारी, वाणी श्रीवास्तव, रियान अहमद, अफान अहमद, अंश यादव, ध्रुवी, अम्रिशा तथा कृष शामिल रहे।

भारत 2027 में एशियन राइफल/पिस्टल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा

नई दिल्ली । एशियन शूटिंग कॉन्फेडरेशन ने बताया है कि भारत साल 2027 में एशियन राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। इस प्रतियोगिता के जरिए लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 के लिए कुल आठ कोटा स्थान मिलेंगे। यह प्रतियोगिता 1 से 10 दिसंबर तक यहां डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित की जाएगी। एशियन राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप 2027 का आयोजन नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा 1 से 10 दिसंबर 2027 तक नई दिल्ली में स्थित डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज में किया जाएगा। एशियन शूटिंग कॉन्फेडरेशन ने एक विज्ञप्ति में कहा कि इस चैंपियनशिप का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है, क्योंकि इस प्रतियोगिता के दौरान लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 के लिए एशिया के आठ कोटा स्थान दिए जाएंगे। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए शूटिंग क्वालिफाइंग प्रतियोगिताओं के ज़रिए अधिकतम 16 कोटा स्थान हासिल किए। इनमें राइफल और पिस्टल स्पर्धाओं में आठ-आठ कोटा शामिल थे। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में रिकॉर्ड 21 निशानेबाजों को भेजा, जो टोक्यो ओलंपिक में भेजे गए 15 निशानेबाजों से काफी ज्यादा था। भारतीय निशानेबाजों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल तीन पदक जीते और तीनों ही कांस्य (ब्रॉन्ज) थे।

पद्म श्री मिलने पर भावुक हुए रोहित शर्मा, बोले- देश को मैच जिताने की कोशिश हमेशा जारी रहेगी

नई दिल्ली। पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म श्री से नवाज़ा गया है। इस सम्मान को लेकर रोहित ने खुशी जताते हुए इसे अपने और अपने परिवार के लिए बेहद खास पल बताया और कहा कि भारत के लिए मैच और ट्रॉफी जीतने की उनकी कोशिश कभी नहीं रुकेगी। पद्म श्री मिलने के बाद रोहित शर्मा ने भारत सरकार और अपने पूरे क्रिकेट सफर में साथ देने वाले लोगों का धन्यवाद किया। दूरदर्शन स्पोर्ट्स द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा किए गए वीडियो संदेश में रोहित ने कहा– 'पद्म श्री प्राप्त करना मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही खास पल है। मैं भारत सरकार का इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त करता हूं। अपने करियर में मेरा साथ देने वाले सभी लोगों का भी धन्यवाद। देश के लिए मैच और ट्रॉफी जीतने की मेरी कोशिश हमेशा जारी रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।' रोहित शर्मा ने वर्ष 2007 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। बीते करीब 19 वर्षों में उन्होंने बल्लेबाज और कप्तान दोनों रूपों में भारतीय क्रिकेट पर गहरी छाप छोड़ी है। सभी प्रारूपों में उनकी निरंतरता और नेतृत्व क्षमता की दुनियाभर में सराहना हुई है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने वैश्विक मंच पर बड़ी सफलता हासिल की।

क्रिकेट जगत को बड़ा झटका: पूर्व क्रिकेटर का 67 साल की उम्र में निधन

लंदन: इंग्लैंड के क्रिकेट गलियारों से एक बेहद दुखद खबर आई है। क्रिकेट के दिग्गज और पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर टोनी पिगॉट ने 67 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह दिया है। टोनी पिगॉट का जाना केवल एक खिलाड़ी का जाना नहीं, बल्कि इंग्लिश काउंटी क्रिकेट के एक ऐसे अध्याय का अंत है जिसने मैदान से लेकर प्रशासन तक अपनी अमिट छाप छोड़ी। टोनी पिगॉट का अंतरराष्ट्रीय करियर आंकड़ों से कहीं ज्यादा उनकी प्रतिबद्धता के लिए याद किया जाएगा। 1983-84 के दौर में जब वह न्यूजीलैंड में क्लब क्रिकेट खेल रहे थे, तब इंग्लैंड की मुख्य टीम चोटिल खिलाड़ियों से जूझ रही थी। टोनी को आनन-फानन में टीम में शामिल किया गया। दिलचस्प और भावुक बात यह है कि जिस समय उन्हें अपना एकमात्र टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला, उसी दौरान उनकी शादी तय थी। उन्होंने देश के लिए खेलने के जुनून में अपनी शादी की तारीख आगे बढ़ा दी।टोनी ने महज 20 साल की उम्र में ससेक्स के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में कदम रखा और अपने पहले ही विकेट को हैट्रिक में बदलकर इतिहास रच दिया।

टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर बोले पैट कमिंस-मेरे पास समय ही कम पड़ गया

एजेंसी

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजी आक्रमण के अगुआ पैट कमिंस ने खुलासा किया है कि वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम का हिस्सा बनने के बेहद करीब थे, लेकिन रिकवरी में हुई मामूली देरी के कारण अंतिम 15 सदस्यीय टीम में जगह नहीं बना सके। पीठ की चोट से जूझ रहे कमिंस को टूर्नामेंट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में बेन ड्वार्शिस ने रिप्लेस किया है।

7 फरवरी से शुरू हो रहे मेगा टूर्नामेंट से बाहर होने पर कमिंस ने कहा कि वह शारीरिक रूप से बेहतर महसूस कर रहे थे, लेकिन पूरी तरह फिट होने के लिए उनके पास पर्याप्त समय नहीं बचा था। कमिंस ने आईसीसी के हवाले से कहा, 'यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण रहा। मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं, बस एक छोटी-सी परेशानी थी और सच कहूं

तो समय ही कम पड़ गया। अब मैं कुछ हफ्तों तक आराम करूंगा और फिर आगे की योजना बऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने बताया कि एडिलेड टेस्ट के बाद मेडिकल टीम ने उनकी पीठ को पूरी तरह ठीक होने के लिए चार से आठ हफ्तों का समय देने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा, 'हमें पता था कि एडिलेड टेस्ट के बाद हड्डी को पूरी तरह स्थिर होने के लिए चार से आठ हफ्तों की जरूरत होगी, उसके बाद ही दोबारा वर्कलोड बढ़ाया जा सकता था। शुरुआत में लगा था कि चार हफ्ते काफी होंगे, क्योंकि मैं अच्छा महसूस कर रहा था, लेकिन फॉलो-अप स्कैन के बाद लगा कि इसे दो हफ्ते और चाहिए। ' कमिंस ने आगे कहा, 'इसके चलते समय-सारिणी बहुत टाइट हो गई और वर्ल्ड कप तक पूरी तरह फिट होना मुश्किल हो गया। ' अब कमिंस को मार्च में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के दौरान प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की उम्मीद है, हालांकि उन्होंने साफ किया कि उनका मुख्य लक्ष्य साल के दूसरे हिस्से में होने वाले अहम टेस्ट मुकाबलों के लिए पूरी तरह फिट रहना है। ऑस्ट्रेलिया के सामने आगे व्यस्त टेस्ट कार्यक्रम है, जिसमें बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू सीरीज, दक्षिण अफ्रीका का दौरा और फिर न्यूजीलैंड व भारत के खिलाफ मुकाबले शामिल हैं, जो मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चक्र का हिस्सा होंगे। कमिंस ने कहा, 'आने वाले क्रिकेट को देखते हुए हमें लगा कि साल के पहले हिस्से में सतर्क रहना सही रहेगा। अगर अभी सावधानी नहीं बरती जाती और चोट दोबारा उभरती, तो मुश्किलें बढ़ सकती थीं। ' वर्ल्ड कप से बाहर रहने के बावजूद कमिंस ने ऑस्ट्रेलियाई टीम पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि हालिया पाकिस्तान के खिलाफ टी20ढ्ढ सीरीज में मिली हार टीम की वास्तविक क्षमता को नहीं दर्शाती।

डीयू से जुड़े कॉलेजों के बीच पद्मश्री श्याम लाल मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट की धमाकेदार शुरुआत

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों के बीच 12वें पद्मश्री श्याम लाल मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट का आगाज शानदार मुकाबलों के साथ हुआ। मेजबान श्याम लाल कॉलेज (प्रातः) और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस (आईजीआई) ने प्रभावशाली जीत दर्ज की। प्रतियोगिता का उद्घाटन दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन ऑफ कॉलेजेस प्रो. बालाराम पाणि ने किया। पहले मुकाबले में श्याम लाल कॉलेज (प्रातः) ने श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज को एकतरफा अंदाज में 8-0 से हराया। टीम की ओर से हरषु ने हैट्रिक लगाई, जबकि आशु ने दो गोल किए। नंद किशोर, प्रवीण और प्रत्यूष ने भी एक-एक गोल दागकर जीत पक्की की।

शानदार प्रदर्शन के लिए हरषु को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। दूसरे मैच में आईजीआई ने हंसराज कॉलेज को 7-1 से पराजित किया। पुलकित ने चार गोल कर मैच पर अपनी छाप छोड़ी, जबकि चंदर, शुभम और गुरमुख ने भी गोल किए। पुलकित को 'प्लेयर ऑफ द मैच' का सम्मान मिला। समारोह के दौरान श्याम लाल कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रो. रबि नारायण कर ने खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताते हुए कॉलेज मैदान में फ्लड लाइट लगाने की घोषणा की, ताकि रात के समय भी खेल आयोजन संभव हो सकें। उन्होंने खेल समिति के संयोजक वी.एस. जग्गी के प्रयासों की सराहना की।

डिफेंडिंग चैंपियन अल्कराज रॉटरडैम ओपन से हटे

एजेंसी

नई दिल्ली। मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज इस साल एबीएन एमरो (रॉटरडैम) ओपन में अपने खिताब का बचाव नहीं करेंगे। टूर्नामेंट आयोजकों ने पुष्टि की कि विश्व नंबर एक अल्कराज एटीपी 500 स्तर के इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। स्पेन के स्टार खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में कड़े अभियान के बाद कुछ समय के लिए ब्रेक लेने का फैसला किया है, जहां उन्होंने मेलबर्न में ऐतिहासिक खिताबी जीत दर्ज की थी। अल्कराज के इस फैसले के साथ ही रॉटरडैम आहोय में उनकी दोबारा मौजूदगी की संभावना समाप्त हो गई है।

उन्होंने 2025 में इसी टूर्नामेंट में एलेक्स डी मिनौर को तीन सेटों में हराकर खिताब जीता था, जो उनके करियर का पहला इंडोर एटीपी खिताब भी था। एबीएन एमरो ओपन के आयोजकों ने एक आधिकारिक बयान में कहा, 'कार्लोस अल्कराज रॉटरडैम में अपने खिताब का बचाव नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन के दौरान पिछले दो हफ्तों में काफी मेहनत के बाद उन्होंने महसूस किया कि उन्हें दोबारा खेलने से पहले

और समय की जरूरत है। हम कार्लोस के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ' अल्कराज का यह फैसला ऑस्ट्रेलियन ओपन में उनकी ऐतिहासिक सफलता के तुरंत बाद आया है, जहां उन्होंने फाइनल में नोवाक जोकोविच को 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 से हराकर पहली बार खिताब जीता था। इस जीत के साथ ही 22 वर्षीय अल्कराज ओपन एरा में सबसे कम उम्र में करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले पुरुष खिलाड़ी भी बन गए।

वॉर्म-अप मैच में इंडिया ए ने अमेरिका को 38 रन से हराया, जगदीशन का शतक और बदोनी की तूफानी पारी

एजेंसी

नई दिल्ली। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के वार्म-अप मुकाबले में इंडिया ए ने डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में यूएसए को 38 रन से हराकर दमदार जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 238 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में यूएसए की टीम 19.4 ओवर में 200 रन पर ऑलआउट हो गई। इंडिया ए की जीत के हीरो एन जगदीशन रहे, जिन्होंने 55 गेंदों में 104 रन की शानदार शतकीय पारी खेली।

उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके और 4 छक्के लगाए तथा 49 गेंदों में शतक पूरा किया। कप्तान आयुष बदोनी ने भी विस्फोटक अंदाज में नाबाद 60 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 26 गेंदों का सामना किया। तिलक वर्मा ने चोट के बाद वापसी करते हुए 38 रन जोड़े, जबकि प्रियांश आर्या ने 13 गेंदों पर 28 रन बनाकर टीम को तेज शुरुआत दिलाई।

239 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए यूएसए की टीम ने संघर्ष

किया, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। गेंदबाजी में रवि बिश्नोई ने 3 विकेट लेकर मैच भारत की ओर मोड़ दिया। खलील अहमद और नमन धीर ने 2-2 विकेट लिए, जबकि बदोनी, तिलक वर्मा और अशोक शर्मा को 1-1 सफलता मिली। मैच में कुल 438 रन बने और दोनों टीमों की ओर से 21 छक्के लगे, जिससे दर्शकों को हाई-स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिला। अब भारतीय सीनियर टीम 4 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना वार्म-अप मैच खेलेगी।

भारत से मैच बॉयकाट पर अड़ा पाकिस्तान, आईसीसी को औपचारिक पत्र भेजने से भी परहेज

एजेंसी

नई दिल्ली। टी20 विश्व कप में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलने के फैसले को लेकर पाकिस्तान अपने सख्त रुख पर कायम दिख रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) फिलहाल इस निर्णय की औपचारिक जानकारी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) को लिखित रूप में देने के पक्ष में नहीं है। रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि चूंकि यह फैसला पाकिस्तान सरकार स्तर पर लिया गया और आधिकारिक मंच के जरिए सार्वजनिक किया गया है, इसलिए अलग से आईसीसी को पत्र लिखने की जरूरत नहीं समझी जा रही। पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में टीम को टूर्नामेंट में भाग लेने की मंजूरी दी थी,

लेकिन भारत के खिलाफ मैच से दूर रहने की बात कही थी। बताया जा रहा है कि पीसीबी इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहता और आगे की रणनीति के लिए विकल्प खुले रखे हुए हैं। दूसरी ओर, आईसीसी पहले ही संकेत दे चुका है कि चयनात्मक भागीदारी टूर्नामेंट के नियमों और खेल भावना के खिलाफ है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत-पाकिस्तान मुकाबला नहीं होता है तो प्रसारण और प्रायोजन से जुड़े पक्षों को बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। यह मैच आम तौर पर आईसीसी टूर्नामेंट्स का सबसे ज्यादा दर्शक जुटाने वाला मुकाबला माना जाता है। इसी बीच पाकिस्तानी टीम श्रीलंका पहुंच चुकी है, जहां वह अपने अन्य मुकाबले खेलेगी।

सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान ने संभावित कानूनी पहलुओं पर भी सलाह ली है और किसी भी आईसीसी कार्रवाई की स्थिति में अपने पक्ष का बचाव करने की तैयारी कर रहा।

दून बलूनी क्रिकेट अकादमी और यूपीईएस ने सेमीफाइनल में बनाई जगह

एजेंसी

देहरादून। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा आयोजित देहरादून डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में दून बलूनी क्रिकेट अकादमी और यूपीईएस ने शानदार जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। पहला क्वार्टर फाइनल राव स्पोर्टिंग क्लब और दून बलूनी क्रिकेट अकादमी के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए राव स्पोर्टिंग क्लब की टीम 20.4 ओवर में 9 विकेट खोकर 99 रन ही बना सकी। टीम की ओर से तनुष गोसाई ने 21, अमन ने 19, प्रियांशु डबराल ने 17 और तुषार ने 15 रन बनाए। गेंदबाजी में दून बलूनी अकादमी के सचिन यादव ने तीन जबकि परितोष ने दो विकेट लिए। जवाब में दून बलूनी क्रिकेट अकादमी ने आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 14.2 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। कार्तिकेय नौटियाल ने 54 और आर्यन शर्मा ने 44 रन की बेहतरीन पारियां खेलीं, जिससे टीम ने 6 विकेट से जीत दर्ज की। राव स्पोर्टिंग क्लब की ओर से ऋषभ बुटोला ने चार विकेट लिए, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सके। दूसरा क्वार्टर फाइनल जीडी गोयंका क्रिकेट ग्राउंड में यूपीईएस और निंबस क्रिकेट अकादमी के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए यूपीईएस ने 25 ओवर में 7 विकेट पर 211 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। विजय शर्मा ने 50, प्रियांक सिंह ने 42, प्रियांशु ने 34, आर्यन कपूर ने 26 और कमल सिंह ने 22 रन का योगदान दिया। निंबस की ओर से हिमांशु और अमन प्रताप सिंह ने दो-दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी निंबस क्रिकेट अकादमी की टीम 24 ओवर में 144 रन पर सिमट गई। शिवांश गौतम ने 74 और अभय राठौर ने 29 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके।

केतन म्हात्रे की तूफानी फिफ्टी बेकार, आखिरी गेंद पर अहमदाबाद लायंस ने 2 रन से जीता रोमांचक मुकाबला

एजेंसी

सूरत। लालभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में खेले गए रोमांचक लीग मुकाबले में अहमदाबाद लायंस ने चेन्नई सिंगम्स को आखिरी गेंद पर 2 रन से हराकर मैच अपने नाम कर लिया। 93 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सिंगम्स जीत के बेहद करीब पहुंची, लेकिन अंत में लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। केतन म्हात्रे की 30 गेंदों पर 54 रन की विस्फोटक पारी भी टीम को जीत नहीं दिला पाई। पहले गेंदबाजी करते हुए चेन्नई सिंगम्स की शुरुआत महंगी रही और शुरुआती ओवरों में रन तेजी से बने। आशीष पाल ने पहला विकेट दिलाकर टीम को राहत दिलाई। इसके बाद जगन्नाथ सरकार ने खतरनाक दिख रहे बल्लेबाज को आउट कर विपक्ष

को दबाव में डाला। मध्य ओवरों में अनुशासित गेंदबाजी से रन गति पर अंकुश लगाया गया। हालांकि अंतिम ओवरों में अमित नाइक ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए अहमदाबाद को 92/5 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। डेथ ओवरों में कुछ किफायती गेंदबाजी जरूर दिखी, लेकिन आखिरी झटके नहीं मिल सके। लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सिंगम्स को शुरुआती झटका जल्दी लग गया। इसके बाद केतन म्हात्रे ने जिम्मेदारी संभाली और तेज बल्लेबाजी से मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने अपनी टीम को मुकाबले में बनाए रखा और तेज अर्धशतक जड़ा। बीच में अमन यादव और मोहम्मद नदीम ने भी उपयोगी योगदान दिया। मैच का निर्णायक मोड़ आखिरी ओवर में आया, जब चेन्नई को जीत के लिए 7 रन चाहिए थे। अहमदाबाद के गेंदबाजों ने दबाव में शानदार संयम दिखाया। आखिरी गेंद पर केतन का विकेट गिरा और टीम लक्ष्य से 2 रन पीछे रह गई। इस करीबी जीत के साथ अहमदाबाद लायंस ने लीग चरण का समापन जीत के साथ किया, जबकि चेन्नई सिंगम्स को हार के बावजूद केतन म्हात्रे की शानदार पारी से सकारात्मक संकेत जरूर मिले।

डबल मुकाबले में शांतम तथा अनिल की जोड़ी 2-0 से जीती

एजेंसी

मुरादाबाद। मुरादाबाद के रेलवे स्टेडियम स्थित बैडमिंटन हॉल मुरादाबाद में अंतर्विभागीय रेलवे बैडमिंटन प्रतियोगिता वर्ष 2026 सीज़न - एक में सोमवार को फाइनल के मुकाबले खेले गए। परिचालन विभाग के शांतम तथा अनिल की जोड़ी ने पहले डबल मुकाबले में विद्युत (परिचालन) के अनुभव व अभिषेक की जोड़ी को 2-0 से हराया तथा सिंगल मुकाबले में शांतम ने अभिषेक को 2-0 से हरा कर विजेता ट्राफी पर कब्जा कर लिया। विद्युत परिचालन उपविजेता बना तथा विद्युत सामान्य विभाग तीसरे स्थान पर रहा।

फाइनल मैच मंडल रेल प्रबंधक विनीत श्रीवास्तव की उपस्थिति में खेले गए। मैच के उपरांत पुरस्कार वितरण मंडल रेल प्रबंधक विनीता श्रीवास्तव

सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता का आयोजन द्वारा किया गया, इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक परितोष गौतम, मण्डल क्रीडा अधिकारी सचिन कुमार तथा संचालन मण्डल क्रीड़ा सचिव राजेंद्र शर्मा द्वारा अपने सहयोगियों के साथ किया गया ।

ताइक्वांडो की भारतीय टीम में मुरादाबाद के आशीष सिंह का चयन

एजेंसी

मुरादाबाद। मुरादाबाद के होनहार खिलाड़ी आशीष सिंह का चयन ताइक्वांडो की भारतीय टीम में किया गया है। वह चार से सात फरवरी तक दुबई में खेली जाने वाली 13 वीं फुजैराह कप अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय टीम की ओर से हिस्सा लेंगे। जिला ताइक्वांडो

स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सचिव शाहवेज अली ने सोमवार को बताया कि आशीष आरएसडी एकेडमी में अभ्यास करते हैं और भारतीय टीम में उनका चयन एसोसिएशन व शहर के लिए गर्व का पल है। शाहवेज अली ने बताया कि आशीष ने हाल ही में जयपुर में आयोजित द्वितीय फेडरेशन कप में रजत पदक भी जीता था और मौजूदा समय में अंडर-37 किग्रा भार वर्ग के कैडेट वर्ग के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं।आशीष के टीम में चयनित होने पर आरएसडी के निदेशक डॉ. विनोद कुमार, डॉ. जी कुमार, डॉ. अजय शर्मा, जिला ताइक्वांडो संघ के पदाधिकारी केशव थापा, सुमित शर्मा, शोभित भारद्वाज, अरविंद सिंह, संदीप कुमार, अर्जुन थापा आदि ने शुभकामनाएं दी हैं।

अजेय भारत की नजर छठे खिताब पर, सेमीफाइनल में अफगानिस्तान से टक्कर

एजेंसी

हरारे : ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अजेय भारतीय टीम बुधवार को अफगानिस्तान के खिलाफ उतरेगी। टूर्नामेंट में अब तक शानदार प्रदर्शन करने वाली भारत की टीम इस मुकाबले में प्रबल दावेदार मानी जा रही है और उसकी नजरें रिकॉर्ड छठा खिताब जीतने की दिशा में एक और कदम बढ़ाने पर होंगी।

भारत -19 वर्ल्ड कप के इतिहास की सबसे सफल टीम है, जिसने 2000, 2008, 2012, 2018 और 2022 में खिताब जीता है। अब टीम बुधवार को छठी बार चैंपियन बनने की ओर कदम बढ़ाने उतरेगी।

अब तक अजेय भारत का दबदबा

भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में अब तक खेले गए अपने सभी पांच मुकाबले काफी सहजता से जीते हैं। सुपर सिक्स चरण में चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 58 रन से हराना टीम के आत्मविश्वास को और मजबूत करता है।

अफगानिस्तान का सफर भी प्रभावशाली

अफगानिस्तान ने भी टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया है। टीम ने पांच में से चार मैच जीते, जबकि उसकी इकलौती हार श्रीलंका के खिलाफ चार विकेट से हुई। हालांकि मौजूदा फॉर्म और टीम संयोजन को देखते हुए नॉकआउट मुकाबले में भारत का पलड़ा भारी नजर आता है।

अभिज्ञान, सूर्यवंशी भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज

विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू भारत के लिए अब तक सबसे सफल बल्लेबाज रहे हैं। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 5 मैचों में 199 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं। ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने भी शानदार फॉर्म दिखाई है। उन्होंने 5 मैचों में 196 रन बनाए हैं और 2 अर्धशतक जड़े हैं। हालांकि टीम प्रबंधन उनसे नॉकआउट मुकाबले में अर्धशतक को शतक में बदलने की उम्मीद करेगा।

विहान मल्होत्रा का ऑलराउंड असर

ऑलराउंडर विहान मल्होत्रा भारत के लिए एक और अहम खिलाड़ी हैं। उन्होंने 5 मैचों में 172 रन बनाए हैं और टूर्नामेंट में भारत की ओर से एकमात्र शतक (109 नाबाद) जिम्बाब्वे के खिलाफ जड़ा था।

कप्तान आयुष म्हात्रे पर दोहरी जिम्मेदारी

कप्तान आयुष म्हात्रे ने गेंदबाजी में निरंतरता दिखाई है। उन्होंने 5 मैचों में 6 विकेट लिए हैं, हालांकि बल्लेबाजी में सुधार की गुंजाइश बनी हुई है। अब तक उनके नाम 99 रन हैं, जिसमें 53 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा है।

गेंदबाजी में हेनिल पटेल और आरएस अंबरीश की अगुआई

भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की कमान दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हेनिल पटेल और आरएस अंबरीश के हाथों में है। दोनों ने शुरुआती ओवरों में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्रमशः 11-11 विकेट झटके हैं।

बाएं हाथ के स्पिनर खिलान पटेल ने भी टूर्नामेंट में शानदार गेंदबाजी की है। उन्होंने 5 मैचों में 8 विकेट लेकर विपक्षी टीमों को परेशान किया है। इसके अलावा कप्तान म्हात्रे और विहान मल्होत्रा भी अपनी ऑफ ब्रेक गेंदबाजी से योगदान देने को तैयार हैं।

मैच का समय

यह सेमीफाइनल मुकाबला बुधवार को दोपहर 1:00 बजे (IST) शुरू होगा।

शेयर बाजार की शानदार वापसी, निवेशकों ने कमाए 4.62 लाख करोड़ रुपये

एजेंसी

नई दिल्ली। बजट वाले दिन रविवार को जोरदार गिरावट का सामना करने के बाद घरेलू शेयर बाजार ने शानदार वापसी की। आज के कारोबार में सेंसेक्स निचले स्तर से 1,300 अंक से अधिक उछल गया। इसी तरह निफ्टी ने भी निचले स्तर से 425 अंक से ज्यादा की छलांग लगाई। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 1.17 प्रतिशत और निफ्टी 1.06 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुए। आज दिन भर के कारोबार के दौरान मेटल, एफएमसीजी और एनर्जी सेक्टर के शेयरों में लगातार खरीदारी होती रही। इसी तरह बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑयल एंड गैस और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इंडेक्स भी मजबूती के साथ बंद हुए। दूसरी ओर, मीडिया, आईटी, टेक और हेल्थ केयर सेक्टर के शेयरों में लगातार बिकवाली का दबाव बना रहा। ब्रॉडर मार्केट में भी आज लगातार खरीदारी होती रही, जिसके कारण बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 0.70 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुआ। इसी तरह स्मॉलकैप इंडेक्स ने 0.30 प्रतिशत की तेजी के साथ आज के कारोबार का अंत किया। आज शेयर बाजार में आई मजबूती के कारण स्टॉक मार्केट के निवेशकों की संपत्ति में साढ़े चार लाख करोड़ रुपये से भी अधिक की बढ़ोतरी हो गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के कारोबार के बाद बढ़ कर 455.23 लाख करोड़ रुपये (अनंतिम) हो गया। पिछले कारोबारी दिन यानी रविवार को इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 450.61 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह निवेशकों को आज के कारोबार से करीब 4.62 लाख करोड़ रुपये का मुनाफा हो गया।

मैरी रिटेल लिमिटेड ने आईपीओ के लिए सेबी के समक्ष डीआरएचपी फाइल किया

नई दिल्ली। हैदराबाद की कंपनी मैरी रिटेल लिमिटेड ने अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिए फंड जुटाने के लिए पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के समक्ष अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) फाइल किया है। मैरी रिटेल लिमिटेड का 2 रुपये फेस वैल्यू वाला ये आईपीओ 522 करोड़ रुपये तक के शेयरों के फ्रेश इश्यू है। इसमें प्रमोटर मैरी वेंकट रेड्डी द्वारा 27,000,000 इक्विटी शेयरों के ऑफर-फॉर-सेल (ओएफएस) शामिल है। कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। कंपनी फ्रेश इश्यू से मिलने वाले 115.6 करोड़ रुपये का इस्तेमाल मैरी रिटेल लिमिटेड के लिए गए सभी या कुछ बकाया कर्जों के पूरे या आंशिक भुगतान/प्री-पेमेंट के लिए करेगी, जबकि 250.5 करोड़ रुपये का इस्तेमाल 10 नए कपड़ों के स्टोर इंटीग्रेटेड रिटेल स्टोर (एसआईएस) के साथ एक नए कपड़ों के स्टोर और दो नए स्टैंडअलोन ज्वैलरी स्टोर खोलने के लिए किए जाने वाले पूंजीगत खर्च के लिए तथा 35.8 करोड़ रुपये का खर्च कंपनी के कुछ मौजूदा स्टोर और वेयरहाउस के लिए लीज/सब-लीज किराए के भुगतान के लिए और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

सरकार बजट सत्र के दूसरे चरण में आईबीसी संशोधन विधेयक पेश करेगी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार दिवालियापन और कर्ज समाधान से जुड़े कानून दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय बजट 2026-27 पेश होने के बाद वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया है कि आईबीसी संशोधन विधेयक को संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में लाया जाएगा। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार की 9 मार्च से शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश करने की योजना है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान यहां कहा कि संसदीय समिति ने दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) से संबंधित प्रस्तावित कानून पर अपनी रिपोर्ट दे दी है। लोकसभा में बजट 2026-27 पेश करने के एक दिन बाद वित्त मंत्री ने बताया कि आईबीसी कानून में बदलाव को लेकर संसदीय समिति पहले ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है। उन?होंने कहा कि इस रिपोर्ट में कानून को और बेहतर बनाने के कई सुझाव दिए गए हैं। सरकार इन सुझावों के आधार पर संशोधन विधेयक तैयार कर रही है।

बजट 2026 पर बजाज ब्रोकिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, मनीष जैन की प्रतिक्रिया

नई दिल्ली। 'कैपिटल मार्केट्स के नजरिए से देखें तो बजट 2026 का फोकस शॉर्ट-टर्म तेजी से ज़्यादा निवेशकों के भरोसे को मजबूत करने पर है। फिस्कल डेफिसिट के तय किए गए रास्ते, रुपये 12.2 लाख करोड़ के कैपेक्स (पूंजीगत खर्च) की मजबूत प्रतिबद्धता और मैन्युफैक्चरिंग आधारित ग्रोथ पर जोर—ये सभी बातें भारत की कुल आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता को दिखाती हैं। कैपिटल मार्केट्स के लिए यह लंबे समय के निवेश और बेहतर विज़िबिलिटी के लिए अनुकूल माहौल बनाता है। कुल मिलाकर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर्स, बायो-फार्मा और स्ट्रैटेजिक मैन्युफैक्चरिंग पर दिया गया फोकस भारत की निवेश कहानी के लिए सकारात्मक है। इससे निवेश के मौके सिर्फ कुछ चुनिंदा सेक्टर्स तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनका दायरा और बढ़ता है। हालांकि कैपिटल मार्केट्स के कुछ सेक्टर्स में लेन-देन की लागत बढ़ने से ट्रेडिंग सेंटिमेंट पर थोड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन लंबे समय के निवेशकों के लिए निरंतरता और फिस्कल डिसिप्लिन कहीं ज़्यादा अहम रहेंगे।

नए निवेश और रोजगार सृजन को गति देगा बजट : दिल्ली मैन्युफैक्चरर्स एसो

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (डीएमए) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रविवार को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए इसे उद्योग जगत के लिए विश्वास, स्थिरता व दीर्घकालिक विकास का बजट बताया। संगठन का मानना है कि बजट की घोषणाओं को समयबद्ध और प्रभावी रूप से लागू किया गया तो यह भारत को उत्पादन, रोजगार और निर्यात के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। एसोसिएशन के चेयरमैन अनिल गुप्ता ने रविवार को कहा कि इस बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को केवल सहायता प्राप्त करने वाला नहीं बल्कि राष्ट्रीय विकास का सक्रिय भागीदार माना गया है। 10,000 करोड़ रुपये के समर्पित

एमएसएमई विकास कोष की घोषणा से उद्योगों को इक्विटी आधारित विस्तार पूंजी उपलब्ध होगी, जो नए निवेश और रोजगार सृजन को गति देगी। इसके साथ ही स्वावलंबी भारत कोष में 2,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान विकासशील उद्योगों को मिश्रित वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। गुप्ता ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा एमएसएमई से की जाने वाली खरीद को व्यापार देय रसीद छूट प्रणाली (टी-रेड्स) मंच पर अनिवार्य करना, समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगा। साथ ही ऋण गारंटी न्यास योजना के अंतर्गत बिना संपार्श्विक कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना एमएसएमई क्षेत्र के लिए बड़ी राहत है। एसोसिएशन के महासचिव विनीत जैन ने कहा कि जीईएम और टी-रेड्स के एकीकरण से ऑर्डर से भुगतान तक पारदर्शी और तेज डिजिटल प्रक्रिया बनेगी। द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के शहरों में प्रस्तावित 'कॉरपोरेट मित्र' पहल से अनुपालन लागत कम होगी और छोटे उद्योगों को सस्ती पेशेवर सहायता मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि कई औद्योगिक कच्चे माल और पुर्जों पर आयात शुल्क में राहत से उत्पादन लागत घटेगी। 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों के पुनर्जीवन की योजना से स्थानीय उद्योगों को नई ऊर्जा मिलेगी। निर्यात उन्मुख एमएसएमई के लिए शुल्क राहत और समयसीमा विस्तार से कार्यशील पूंजी पर दबाव कम होगा। सेवा क्षेत्र के लघु उद्योगों के लिए देखभाल अर्थव्यवस्था, चिकित्सा मूल्य पर्यटन, एवीजीसी (एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स), डिजाइन तथा पर्यटन जैसे क्षेत्रों में नए अवसर खुलेंगे, जिससे रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।

चिराग पासवान ने प्रसंस्कृत खाद्य के बारे में गलत जानकारी का मुकाबला करने का आह्वान किया

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने प्रोसेस्ड फूड्स (प्रसंस्कृत खाद्य) के बारे में गलत जानकारी का मुकाबला करने का आह्वान किया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में प्रसंस्कृत खाद्य से जुड़े गुमराह करने वाले प्रचार का मुकाबला करने के लिए बनाई गई कमेटी की दूसरी बैठक की अध्यक्षता के दौरान अपने संबोधन में यह बात कही। इस बैठक में कमेटी के सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग जगत के नेता और इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि इस बैठक में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि फूड प्रोसेसिंग खाने की सुरक्षा, पोषण, बर्बादी कम करने और किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। उन?होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रोसेस्ड फूड के बारे में फैले मिथकों और गलत जानकारियों को साइंस पर आधारित बातचीत, पारदर्शिता और जिम्मेदार जुड़ाव के जरिए सक्रिय रूप से दूर किया जाना चाहिए। चिराग पासवान ने एक संतुलित पब्लिक राय बनाने और यह पक्का करने के लिए कि फूड प्रोसेसिंग के बारे में सही और भरोसेमंद जानकारी हर नागरिक तक पहुंचे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म और दूसरे बड़े कम्युनिकेशन चैनलों का इस्तेमाल करने के महत्व पर ज़ोर दिया। इसके साथ ही सभी स्टेकहोल्डर्स की सामूहिक ज़िम्मेदारी पर भी जोर दिया।

हरियाणा में व्यापार होगा आसान

एजेंसी

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने व्यापार सुगमता को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन रूल्स, 2016 में अहम संशोधनों को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में रात हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसके तहत अब जिला एमएसएमई केंद्र के संयुक्त निदेशक/उप निदेशक को जिला स्तरीय क्लीयरेंस समिति का सदस्य बनाया गया है। राज्य सरकार ने हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन एक्ट, 2016 और उससे जुड़े नियम इसलिए बनाए थे ताकि निवेश प्रक्रियाओं में देरी कम की जा सके। उद्यमियों की लागत को घटाया जा सके, और एक ऐसा व्यवसाय-अनुकूल इकोसिस्टम विकसित हो जो श्रेष्ठ मानकों के अनुरूप हो। अब किए गए संशोधन इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और जिला स्तर पर एमएसएमई सेक्टर की भूमिका को और अधिक सशक्त बनाते हैं। हर जिले में बनी जिला स्तरीय क्लीयरेंस समिति का गठन अधिनियम की धारा

8 के तहत किया गया है, जो उद्योगों से जुड़े विभिन्न अनुमोदन और क्लीयरेंस को समयबद्ध तरीके से मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है। एमएसएमई केंद्र के अधिकारी को समिति में शामिल किए जाने से जिलों में चल रही एमएसएमई योजनाओं की गति तेज होगीः छोटे और मध्यम उद्यमों की चुनौतियों का समाधान स्थानीय स्तर पर और तुरंत किया जा सकेगा और क्लीयरेंस प्रक्रिया में विशेषज्ञ दृष्टिकोण जुड़ेगा।

राज्य में प्रत्येक जिले में काम कर रहे जिला एमएसएमई केंद्र पहले ही सलाह, प्रशिक्षण, सहायता और योजनाओं की मंजूरी में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। अब उन्हें नीति-स्तर पर भी अधिक अधिकार मिलेंगे। एमएसएमई विभाग को उद्यमियों की सहायता, मार्गदर्शन और ग्राउंड-लेवल समस्याओं के समाधान के लिए बनाया गया था। समिति में शामिल होने के बाद शिकायतों का निपटारा तेज होगा। योजना अनुमोदन आसान होगा और उद्यमियों को जरूरी क्लीयरेंस तेजी से मिल सकेंगे।

एआई सम्मेलन के लिए 35 हजार पंजीकरण और 100 देशों की भागीदारी

एजेंसी

नई दिल्ली। नई दिल्ली में आगामी 16-20 फरवरी 2026 तक आयोजित होने वाला 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक एआई सम्मेलन बनने जा रहा है। इसके लिए 35 हजार से अधिक पंजीकरण प्राप्त हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार यह सम्मेलन जिम्मेदार, समावेशी और प्रभाव-संचालित एआई के आसपास बढ़ती अंतरराष्ट्रीय गति को दर्शाएगा। इसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। 15-20 राष्ट्राध्यक्ष और 50 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मंत्रियों की उपस्थिति रहेगी। इसके अलावा दुनिया भर की दिग्गज कंपनियों के 40 से अधिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और 500 से अधिक एआई विशेषज्ञ शिरकत करेंगे। सम्मेलन केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि नवाचार का प्रदर्शन भी

करेगी। आयोजन के दौरान 500 से अधिक एआई स्टार्टअप्स अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान कुल 500 सत्र आयोजित किए जाएंगे, जो एआई पर केंद्रित दुनिया का सबसे व्यापक आयोजन बन जाएगा। अब तक 500 से अधिक प्री-समिट कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 3 लाख से अधिक लोगों ने भागीदारी की है। ब्लेचले पार्क (खतरा), सियोल (नैतिकता) और पेरिस (सिद्धांत) के बाद, अब नई दिल्ली का यह सम्मेलन 'एआई के प्रभाव और क्रियान्वयन' पर केंद्रित है। यह वैश्विक स्तर पर एआई नीतियों को आकार देने में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। समिट को कवर करने के लिए मीडियाकर्मी 08 फरवरी तक इसके आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। सम्मेलन के एजेंडा और फोकस क्षेत्रों की विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

पश्चिम बंगाल के लिए 14 हजार 205 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधानः अश्वनी वैष्णव

एजेंसी

खड़गपुर। केंद्रीय बजट 2026-27 में भारतीय रेलवे को अब तक का सर्वाधिक दो लाख 78 हजार करोड़ रुपये आवंटन किए गए हैं। इस बजट में रेलवे सुरक्षा, माल परिवहन और उच्च गति रेल संपर्क को प्राथमिकता दी गई है। पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा को इस बजट में विशेष लाभ मिला है। यह जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित प्रेस वार्ता में दी। रेल मंत्री ने बताया कि पश्चिम बंगाल के लिए 14 हजार 205 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है, जो 2009 से 2014 के दौरान किए गए आवंटन की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है। राज्य में 101 रेलवे स्टेशनों को 'अमृत स्टेशन' के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में लगभग 92 हजार 974 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जिनमें नई रेल लाइनों का निर्माण,

स्टेशन पुनर्विकास तथा सुरक्षा से जुड़े कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में वर्तमान में नौ जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस, एक जोड़ी वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस तथा 11 जोड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन हो रहा है। बीते दस वर्षों में राज्य में लगभग 1400 किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाई गई हैं तथा शत-प्रतिशत रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य भी पूरा कर लिया गया है। बजट में वाराणसी-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, जिससे पश्चिम बंगाल को पहली बुलेट ट्रेन की सुविधा प्राप्त होगी। इसके अलावा दानकुनी से सूरत तक नया फ्रेट कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जिससे माल परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। राज्य में 3200 रूट किलोमीटर में 'कवच' सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने की स्वीकृति भी दी गई है। वहीं, ओडिशा के लिए बजट में 10 हजार 928 करोड़ रुपये तथा झारखंड के लिए सात हजार 536 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। दोनों राज्यों में भी अमृत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन विकास, वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार के व्यापक कार्य जारी हैं। खड़गपुर मंडल के रेल प्रबंधक ललित मोहन पांडेय ने मीडिया को बताया कि कांति-एगरा, नंदकुमार-बलाइपांडा तथा नंदीग्राम-कांदियामारी नई रेल लाइन परियोजनाओं को रेलवे बोर्ड ने डीफ्रीज कर दिया है और शीघ्र ही इन पर कार्य प्रारंभ होगा। उन्होंने कहा कि मंडल में उपनगरीय और एक्सप्रेस ट्रेनों की समयपालन व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा यात्री सुविधाओं में निरंतर सुधार किया जा रहा है।

डीजल लोकोमोटिव लीजिंग और रखरखाव के लिए सेल और राइट्स ने किया समझौता

एजेंसी

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील उत्पादक कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने अपने संयंत्रों और खानों में लॉजिस्टिक्स और परिचालन दक्षता को मजबूत करने के लिए नवरत्न उपक्रम राइट्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौता ज्ञापन पर सेल की ओर से कार्यपालक निदेशक (प्रचालन) पीके बैसाखिया और राइट्स की ओर से कार्यपालक निदेशक (तकनीकी सेवाएं) संदीप जैन ने सेल और राइट्स के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। इस सहयोग का मकसद सेल के प्लांट्स और माइंस में उसके डीजल लोकोमोटिव फ्लीट के ऑपरेशन और मेंटेनेंस को बेहतर बनाना है।

इस्पात मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की ओर अपनी गति को तेज कर रहा है। इसी तरह राइट्स लिमिटेड डीजल लोकोमोटिव संचालन और रखरखाव में मूल्यवान विशेषज्ञता प्रदान करना जारी रखे हुए है, जो सेल के डीजल बेड़े को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। भारतीय रेलवे की सुविधाओं, स्पेयर पार्ट्स और कुशल जनशक्ति के पूल की पहुंच के साथ राइट्स सेल की परिचालन आवश्यकताओं को लागू करने और इसके नेटवर्क में विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। यह सहयोग दोनों संगठनों को अपनी मुख्य दक्षताओं पर ध्यान केंद्रित करने, लागत को अनुकूलित करने, परिचालन दक्षता बढ़ाने और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में योगदान देने में सक्षम बनाएगा।

केंद्रीय बजट में छत्तीसगढ़ में रेलवे के विकास के लिए 7470 करोड़ रुपये आवंटित

एजेंसी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में रेलवे अधोसंरचना विकास के लिए 7,470 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक बजट प्रावधान किए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि डबल इंजन सरकार के सतत प्रयासों से छत्तीसगढ़ में आज रेलवे क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। वर्ष 2009-14 के दौरान वार्षिक औसत 311 करोड़ रुपयेकी तुलना में 2026-27 में ?7,470 करोड़ का बजट प्रावधान लगभग 24 गुना वृद्धि का रिकॉर्ड है। वर्तमान में राज्य में 51,080 करोड़ रुपये के रेल कार्य प्रगति पर हैं, जिनमें नए ट्रैक निर्माण, स्टेशनों का पुनर्विकास तथा सुरक्षा उन्नयन जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल

हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुदूर वनांचल बस्तर में जगदलपुर को जोड़ने वाले रावघाट-जगदलपुर रेल प्रोजेक्ट का प्रारंभ होना बस्तर के जनजातीय समाज के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक अमूल्य उपहार है, जो क्षेत्रीय विकास की नई राह प्रशस्त करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि परमलकसा-खरसिया कॉरिडोर के साथ-साथ नए फ्रेट कॉरिडोर को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में यात्री गाड़ियों की संख्या आने वाले समय में लगभग दोगुनी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत राज्य के 32 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिनमें डोंगरगढ़ (फेज-द्ब), अंबिकापुर, भानुप्रतापपुर, भिलाई और उरकुरा जैसे स्टेशन पूर्ण हो चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में वंदे भारत एक्सप्रेस की 2 जोड़ी तथा अमृत भारत एक्सप्रेस की 1 जोड़ी सेवाएँ यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक रेल सुविधा प्रदान कर रही हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक लगभग 1,200 किलोमीटर नए रेल ट्रैक का निर्माण, 100 प्रतिशत विद्युतीकरण, 170 फ्लाईओवर/अंडरपास तथा 'कवच' जैसी आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों की स्थापना से रेल सुविधा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इन युगांतकारी पहलों के लिए हृदय से धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि यह विकास केवल रेल पटरियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे प्रदेश के व्यापार, पर्यटन, उद्योग, रोजगार और आमजन के जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है।

पूर्वोत्तर के लिए रेलवे का बड़ा तोहफा, 11,486 करोड़ का बजट आवंटन

एजेंसी

कटिहार। असम और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भारतीय रेलवे का 2026-27 का बजट आवंटन एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। भारत सरकार ने इस क्षेत्र के लिए रिकॉर्ड 11,486 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं, जो 2014 की तुलना में लगभग पाँच गुना अधिक है।

कटिहार रेल मंडल के डीआरएम किरेंद्र नरह ने सोमवार शाम बताया कि असम और पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा विकास चल रहा है, जिसमें 72,468 करोड़ रुपये की रेल परियोजनाएँ प्रगति पर हैं। नई रेल लाइनों का सर्वे किया जा रहा है और कोकराझार से भूटान के गेलेफू तक रेल कनेक्टिविटी की योजना बनाई जा रही है। असम में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेवाएं शुरू की गई हैं, जो कामाख्या-हावड़ा मार्ग पर चलती हैं। इसके अलावा, असम के पहले अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवाएं भी शुरू हुई हैं, जो गुवाहाटी-रोहतक और डिब्रूगढ़-लखनऊ मार्गों पर चलती हैं। वाराणसी-सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा गया है और भविष्य में इसे गुवाहाटी तक बढ़ाने की योजना है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने असम और पूर्वोत्तर में रेल नेटवर्क का विस्तार और बिजलीकरण तेजी से किया है,

जिसमें लगभग 1900 कि.मी. नई पटरियाँ बिछाई गई हैं और पांच राज्य पूर्ण विद्युतीकृत हो चुके हैं। इस बजट आवंटन से असम और पूर्वोत्तर राज्यों में रेल कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।

बैंक सम्पत्तियों की नीलामी के लिए सरकारी बैंकों के साझा मोबाइल ऐप का उद्घाटन

एजेंसी

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू ने सोमवार को यहां सरकारी क्षेत्र के बैंकों की एक बैठक में बैंकों की सम्पत्तियों की नीलामी के लिए मोबाइल ऐप 'बैंकनेट' और डिजिटल बैलेंस कन्फर्मेशन प्लेटफॉर्म (डीबीसीपी) का उद्घाटन किया। श्री नागराजू ने पीएसबी एलायंस की वार्षिक रणनीति बैठक में बैंकों के शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) और लागत बनाम कमाई अनुपात को सुधारने में सकारात्मक योगदान देने में पीएसबी एलायंस की भूमिका पर भी जोर दिया गया। उन्होंने कहा, 'यह देखा गया कि जबकि बैंकनेट पहले ही बैंक नीलामी संपत्तियों में संरचना और पारदर्शिता ला चुका है, नया मोबाइल ऐप सत्यापित बैंक संपत्तियों तक पहुंच को वास्तव में राष्ट्रव्यापी और चलते-फिरते सुलभ बनायेगा। ' उन्होंने कहा कि यह ऐप आम नागरिकों को सशक्त बनायेगा और बैंकों को तेजी से रिकवरी हासिल करने में सहायता करेगा। श्री नागराजू ने डीबीसीपी को ऑडिट प्रक्रिया में अधिक दक्षता और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि इसका अंतिम लक्ष्य मैनुअल बैलेंस कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट को पूरी तरह से समाप्त करना है। उन्होंने सरकारी बैंकों के इस एलायंस को अपने साझा सेवा पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार सरकारी बैंकों के बाहर भी ले जाने की सलाह दी।

पूर्वोदय विजन की धुरी बना बंगाल : बजट ने खोले इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्यात के नए रास्ते

एजेंसी

कोलकाता। केंद्र सरकार के आम बजट 2026-27 में चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल को इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, निर्यात और सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर कई अहम सौगातें मिली हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए राज्य के लिए फ्रेट कॉरिडोर, हाई-स्पीड रेल, औद्योगिक कॉरिडोर, एमएसएमई सहायता और चाय श्रमिकों के कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों की घोषणा की। अब एक दिन बाद इस पर पश्चिम बंगाल के औद्योगिक विश्लेषकों ने विस्तार से अपनी राय रखी है। निर्यात क्षेत्र को बड़ी राहतबजट में निर्यात क्षेत्र के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए उपयोग होने वाले कच्चे माल पर ड्यूटी-फ्री आयात की सीमा को पहले के एक प्रतिशत से बढ़ाकर तीन प्रतिशत कर दिया गया है। यह सीमा पिछले वर्ष के निर्यात कारोबार के एफओबी मूल्य के आधार पर तय होगी। इसके अलावा, लेदर या सिंथेटिक फुटवियर के साथ-साथ अब शू अपर के निर्यात पर भी ड्यूटी-फ्री आयात की सुविधा दी गई है। लेदर और टेक्सटाइल गारमेंट्स तथा लेदर और सिंथेटिक फुटवियर निर्यातकों को अब अंतिम उत्पाद के निर्यात के लिए छह महीने की जगह एक वर्ष का समय मिलेगा।

पश्चिम बंगाल से समुद्री उत्पाद और लेदर का संयुक्त निर्यात 13 से 15 हजार करोड़ रुपये के बीच है, जिससे शहरी और तटीय ग्रामीण जिलों में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। अर्जुन कुलकर्णी, इंडियन लेदर प्रोडक्ट्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि इस फैसले से लेदर निर्यात में दो से तीन प्रतिशत तक मार्जिन बेहतर होगा। उन्होंने बताया कि लेदर निर्यात में आयातित कच्चे माल की हिस्सेदारी 10 से 12 प्रतिशत तक होती है। वहीं, सीफूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय प्रबंध समिति के सदस्य राजर्षि बनर्जी ने कहा कि यह कदम स्वागत योग्य है, लेकिन समुद्री उत्पाद क्षेत्र के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इस सेक्टर में आयात लागत बड़ा कारक नहीं होती। चाय उद्योग और श्रमिकों को राहतबजट में चाय उद्योग से जुड़े श्रमिकों की बेहतरी पर भी ध्यान दिया गया है। पश्चिम बंगाल के चाय उद्योग ने प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना को एक और वर्ष के लिए बढ़ाए जाने का स्वागत किया है। इस योजना से खासतौर पर महिला और बच्चों को लाभ मिलेगा। हालांकि, बजट में असम के चाय बागान श्रमिकों के लिए परिवार पेंशन और जीवन बीमा से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की घोषणा भी की गई है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों में श्रमिक कल्याण को बल मिलेगा। फ्रेट कॉरिडोर और हाई-स्पीड रेल से बदलेगा कनेक्टिविटी का नक्शाइंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर बजट में पश्चिम बंगाल के लिए दो बड़े ऐलान किए गए हैं। पहला, हुगली जिले के डानकुनी से गुजरात के सूरत तक एक समर्पित फ्रेट कॉरिडोर का प्रस्ताव है। इससे पूर्वी भारत के उद्योगों के लिए लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा अहम प्रस्ताव सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का है। इनमें एक हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी को जोड़ेगा। यह कॉरिडोर प्रमुख आर्थिक केंद्रों, आईटी हब, औद्योगिक क्लस्टर और उभरते शहरों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा।बजट में एकीकृत ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी घोषणा की गई है, जिसमें दुर्गापुर को एक प्रमुख औद्योगिक नोड के रूप में विकसित किया जाएगा।

नाइजर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस्लामिक स्टेट का आत्मघाती हमला

एजेंसी

नियामी (नाइजर)। अफ्रीकी देश नाइजर की राजधानी नियामी में स्थित डियोरी हमानी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इस्लामिक स्टेट (IS) के आतंकवादियों ने भीषण हमला किया है। जारी एक चौंकाने वाले वीडियो में भारी हथियारों से लैस आतंकी रनवे पर यात्री विमानों के पास खुलेआम फायरिंग करते और एक हेलिकॉप्टर व ड्रोन को आग के हवाले करते नजर आ रहे हैं। इस अचानक और समन्वित हमले में नाइजर के चार सैनिकों की मौत हो गई, जबकि जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 20 हमलावरों को ढेर कर दिया। हमले के दौरान हुए तेज धमाकों और गोलीबारी से घंटों तक पूरे एयरपोर्ट परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। SITE इंटेलिजेंस ग्रुप द्वारा जारी वीडियो फुटेज का विश्लेषण करने पर विशेषज्ञों ने पाया कि हमलावर 'कनुरी' भाषा बोल रहे थे, जो मुख्य रूप से लेक चाड क्षेत्र में सक्रिय 'इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस' के लड़ाकों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। इससे संकेत मिलता है कि इस हमले को अनुभवी आतंकियों द्वारा बेहद सावधानी से प्लान किया गया था। हमले की चपेट में आने से पैन-अफ्रीकी एयरलाइन (ASKY) और एयर कोटे डी आइवर के कई विमानों को नुकसान पहुँचा है। हालांकि, राहत की बात यह रही कि यह हमला परिचालन समय के बाहर हुआ, जिससे किसी यात्री या चालक दल के सदस्य की जान नहीं गई।

यूएई ने अज़रबैजान से सदर्न गैस कॉरिडोर में हिस्सेदारी के लिए समझौता किया

अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडीएनओसी) की सहायक कंपनी एक्सआरजी ने सदर्न गैस कॉरिडोर में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अजरबैजान अर्थव्यवस्था मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए है। अमीरात मीडिया ने यह जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समाचार एजेंसी ने बताया कि यह समझौता कई शर्तों पर निर्भर है, जिसमें नियमित नियामक और विश्वास विरोधी मंजूरी हासिल करना शामिल है। हासिल की जा रही हिस्सेदारी की जानकारी का खुलासा नहीं किया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि सदर्न गैस कॉरिडोर में प्राकृतिक गैस उत्पादन संपत्तियां और कैस्पियन सागर से जॉर्जिया और तुर्की होते हुए दक्षिणी यूरोप तक 3,500 किलोमीटर का पाइपलाइन नेटवर्क शामिल है, जिसकी मौजूदा आपूर्ति क्षमता हर साल 26 बिलियन क्यूबिक मीटर तक है।

वैश्विक मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करना गर्व की बात-थॉमसन

कोट्टायम। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग की प्रथम सचिव रोशनी थॉमसन ने कहा है कि वैश्विक मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करना बहुत गर्व की बात है और एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है। सुश्री थॉमसन अल्फोंसा कॉलेज, पाला में आयोजित 'मीट द डिप्लोमैट' कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत कर रही थीं। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि राजनयिक सेवा का सबसे बड़ा सम्मान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश के लिए बोलना है। 'भारत' के नामपट्ट के पीछे बैठकर देश के विचारों को व्यक्त करने के लिए आत्मविश्वास, स्पष्टता और राष्ट्रीय हितों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता की ज़रूरत होती है। उन्होंने बताया कि राजनयिकों पर भारत की विदेश नीति की स्थितियों और दृष्टिकोणों को दूसरे देशों के सामने सही और भरोसेमंद तरीके से पेश करने की ज़िम्मेदारी होती है। उन्होंने विदेश सेवा अधिकारियों की भूमिका और काम करने के तरीके के बारे में बताते हुए कहा कि कूटनीति में लगातार सीखने और ढलने की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा कि स्थानीय माहौल से करीब से जुड़कर ही राजनयिक भारत के रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा कर सकते हैं और देशों के बीच संबंधों को मज़बूत करने में सार्थक योगदान दे सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय अधिकारियों को अक्सर राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करने वाले वैश्विक घटनाक्रमों पर तेज़ी से और सोच-समझकर जवाब देने की ज़रूरत होती है।

मेडागास्कर : फितिया तूफान में सात मरे, 54000 प्रभावित

एंटानानारिवो। मेडागास्कर के अधिकारियों ने बताया कि फितिया चक्रवाती तूफान में सात लोगों की मौत हो गयी है, जबकि 54,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय जोखिम एवं आपदा प्रबंधन कार्यालय ने अपने नवीनतम बुलेटिन में बताया कि उत्तर-पश्चिमी इलाकों और राजधानी एंटानानारिवो में तूफान से 1,400 से ज़्यादा घर तबाह हो गए और 9,000 से ज़्यादा घरों में पानी भर गया। कुल 27 जिले इस चक्रवात से प्रभावित हुए, जो शनिवार सुबह पश्चिम से मेडागास्कर से टकराया और रविवार को पूर्वी तट पर स्थित शहर वाटोमांड्री से होते हुए समुद्र में चला गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तरी और मध्य-पश्चिमी इलाकों में और बारिश होने का अनुमान लगाया है।

नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय की निपाह वायरस से सतर्क रहने की अपील

एजेंसी

काठमांडू। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को निपाह वायरस को लेकर नागरिकों से घबराने के बजाय सतर्क और जिम्मेदार रहने की अपील की है। मंत्रालय ने बयान में कहा कि कुछ देशों में निपाह वायरस के मामलों से वह अवगत है। इससे निपटने के लिए सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने कहा कि एहतियात के तौर पर महामारी विज्ञान एवं रोग नियंत्रण प्रभाग (ईडीसीडी) ने देशभर के स्वास्थ्य संस्थानों और संबंधित एजेंसियों को सतर्क कर दिया है तथा निपाह वायरस की जांच के लिए व्यवस्था की गई है। यह वायरस संक्रमित चमगादड़ों के मूत्र, मल या लार से दूषित फलों के सेवन के माध्यम से फैल सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागरिकों से

मानक स्वास्थ्य उपाय अपनाने का आग्रह किया है। इनमें फलों को अच्छी तरह धोकर सेवन करना, सब्जियों को अच्छी तरह पकाकर खाना, उबला या सुरक्षित पानी पीना, पशुशालाओं और खेतों में स्वच्छता बनाए रखना, दस्ताने और मास्क जैसे सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग करना, साबुन और पानी से बार-बार हाथ धोना तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों में मास्क पहनना शामिल है।मंत्रालय ने सलाह दी है कि बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, चक्कर आना, खांसी, सांस लेने में कठिनाई, मतली, उल्टी या गंभीर मामलों में बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई देने पर संबंधित व्यक्ति को अलग रखा जाए और तुरंत सूचना दी जाए। संदिग्ध लक्षण महसूस होने पर नजदीकी स्वास्थ्य संस्थान से संपर्क करें या स्वास्थ्य हॉटलाइन 1115 पर कॉल करें। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि नेपाल में अब तक निपाह वायरस का कोई पुष्ट मामला सामने नहीं आया है और किसी भी संभावित जोखिम को न्यूनतम करने के लिए स्वास्थ्य प्राधिकरण पूरी तरह तैयार हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय साझेदार संस्थाओं के समन्वय में स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है तथा नागरिकों से अफवाहों से बचने और केवल मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने की अपील की है। उल्लेखनीय है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने वैश्विक स्तर तथा दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में निपाह वायरस से जुड़े समग्र स्वास्थ्य जोखिम को कम आंका है, फिर भी भारत में सामने आए मामलों को देखते हुए मंत्रालय ने तैयारी और जन-जागरूकता के उपायों को और सुदृढ़ किया है।

आयोग ने समानुपातिक सूची से 76 उम्मीदवारों का नाम हटाया

एजेंसी

काठमांडू। निर्वाचन आयोग ने पांच मार्च को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत समानुपातिक प्रतिनिधित्व की बंद सूची से 76 उम्मीदवारों के नाम हटाने का निर्णय लिया है। आयोग ने कहा कि उम्मीदवारों का विवरण सत्यापित करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। हटाए गए उम्मीदवारों में से 21 उम्मीदवार क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो नेपाल (सीआईबी नेपाल) की ब्लैकलिस्ट में पाए गए। इसके अलावा, 25 उम्मीदवार ऐसे पाए गए जिनके नाम एक साथ प्रांतीय सभा सदस्यता की समानुपातिक बंद सूचियों में भी शामिल थे। इसी तरह, आयोग द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान न करने वाले 10 उम्मीदवारों, न्यूनतम 25 वर्ष की आयु पूरी न करने वाले चार उम्मीदवारों तथा मतदाता नामावली में नाम दर्ज न होने वाले एक उम्मीदवार का नाम भी सूची से हटाया गया है। इसके अतिरिक्त, दो उम्मीदवार ऐसे पाए गए जो पिछड़े क्षेत्र से संबंधित नहीं थे, इसके बावजूद उन्हें उसी श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था। एक पुरुष उम्मीदवार का नाम महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित कोटे में शामिल किया गया था। वहीं, संबंधित राजनीतिक दलों के अनुरोध पर 10 उम्मीदवारों के नाम हटाए गए हैं। आयोग ने बताया कि दो उम्मीदवारों को एक से अधिक कारणों के आधार पर अपात्र घोषित किया गया है।

प्रचंड की पार्टी ओली से कोई चुनावी तालमेल नहीं करेगी

एजेंसी

काठमांडू। पूर्व प्रधानमंत्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचंड' ने कहा कि इस चुनाव में केपी शर्मा ओली के साथ कोई चुनावी तालमेल नहीं होगा। उन्होंने आज काठमांडू में पत्रकारों से कहा कि वे सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से संवाद कर रहे हैं। ओली का नाम लेकर प्रचंड ने कहा कि उनके साथ चुनावी तालमेल की कोई संभावना नहीं है।

प्रचंड ने कहा, 'मैं यह बात पूरी स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि मेरी बातचीत राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (रास्वपा) के नेताओं से भी हो रही है और कांग्रेस के नेताओं से भी। कल शेरबहादुर देउवाजी से मुलाकात हुई। आज गगन थापा से भी बातचीत जारी है। केपी ओली से बातचीत करने का मतलब यह नहीं कि कोई सिद्धांत या पहचान खत्म हो जाती है। सभी से संवाद हो रहा है और होता रहेगा। 'उन्होंने कहा कि इस बार पार्टी ने सभी 165 निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। कहीं भी कोई चुनावी तालमेल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा 'सभी से बातचीत करना मेरी विशेषता है। मैं सहज रूप से संवाद करता हूं।'

झापा में केपी ओली को समर्थन करने के सवाल पर प्रचंड ने कहा कि राजनीति में कुछ भी पूरी तरह

असंभव नहीं होता, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने कहा 'अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। केपी ओली से कभी फोन पर, कभी प्रत्यक्ष मुलाकात में चर्चा होती रहती है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इस दौरान शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, रवि लामिछाने समेत कई नेताओं से उनकी मुलाकातें हुई हैं। बालेन शाह के पिता के निधन के समय वे उनके घर जाकर संवेदना व्यक्त करने और बातचीत करने भी गए थे। 'देश कठिन दौर में है। परिवर्तन की जिम्मेदारी निभाने के नाते मैंने कई लोगों से संवाद किया है,' प्रचंड ने कहा। रुकुम पश्चिम में केपी ओली द्वारा उनके खिलाफ अन्य दलों से तालमेल करने के सवाल पर प्रचंड ने कहा कि इससे ओली की सोच झलकती है। उन्होंने बताया कि इस विषय पर उन्होंने ओली से सीधे सवाल भी किया था। बातचीत के बाद ओली ने पूर्वी रुकुम में दिए गए समर्थन को वापस लेकर अपने उम्मीदवार को बरकरार रखा, हालांकि यह प्रचंड के समर्थन में नहीं था।

एमाले या कांग्रेस के साथ मिलकर फिर से नंबर एक पार्टी बनने की संभावना के सवाल पर प्रचंड ने दो टूक कहा, 'न तो एमाले के साथ और न ही कांग्रेस के साथ–कोई समीकरण नहीं है। यह बिल्कुल साफ है। जनता को किसी भी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। हम अकेले जाएंगे, 'नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी' के रूप में 165 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और मुझे विश्वास है कि इस बार भी हम अच्छे नतीजों के साथ नंबर एक पार्टी बनने की मजबूत संभावना रखते हैं।'

पीएम उम्मीदवार बालेन शाह से नेपाल निर्वाचन आयोग ने दूसरी बार मांगा जवाब

एजेंसी

काठमांडू। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (रास्वपा) की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और झापा-5 के उम्मीदवार बालेन्द्र शाह (बालेन) से निर्वाचन आयोग ने दूसरी बार स्पष्टीकरण मांगा है। आयोग ने शाह से तीन दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। आयोग के अनुसार सादे कपड़ों में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा बालेन के पक्ष में वोट मांगने से संबंधित सामग्री प्राप्त होने के कारण दूसरी बार स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान शाह की पत्नी के साथ सादे कपड़ों में पुलिस तैनात किए जाने के संबंध में क्या और कैसे हुआ, इस बारे में भी आयोग ने स्पष्टीकरण मांगा है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में अन्य नौ लोगों से भी स्पष्टीकरण मांगा है। आयोग के सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसी के अनुसार बाजुरा में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार हेमराज थापा के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत में आरोप है कि पीएस बानियां जेवी द्वारा ठेके पर लिए गए मार्तडी-कोल्टी सड़क निर्माण परियोजना के मुद्दे को जोड़ते हुए थापा ने बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री इन्द्रबहादुर बानियां को निशाना बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय में अपमानजनक और धमकीपूर्ण भाषा का प्रयोग किया, साथ ही इस संबंध में सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया। इसी आधार पर उम्मीदवार थापा से यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि क्या उन्होंने बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री बानियां के खिलाफ अपमानजनक, धमकीपूर्ण और अपशब्दयुक्त अभिव्यक्ति दी है या नहीं। इसके अलावा शिकायत में उल्लेख के अनुसार आर्थिक संसाधन एकत्र करते समय उन्होंने निर्वाचन आचार संहिता, 2025 के प्रावधानों का पालन किया है या नहीं, इस पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। प्रवक्ता जिसी ने बताया कि निर्वाचन आचार संहिता, 2025 की धारा 21 के खंड (च) तथा धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (च) और (ज) के तहत बाजुरा के उम्मीदवार थापा से तीन दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। चुनाव उम्मीदवारों को लक्षित भ्रामक और अमर्यादित संदेशों के प्रकाशन व प्रसारण से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों और संचार माध्यमों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आयोग ने प्रेस काउंसिल नेपाल को पत्र भी भेजा है। इसके अलावा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। आरोप है कि पार्टी ने निर्वाचन आचार संहिता के प्रतिकूल प्रतिनिधि सभा सदस्य सिंधुपालचोक जिला निर्वाचन क्षेत्र संख्या-1 के निर्वाचन कार्यालय के बाहर अपने दल का चुनाव चिह्न पेंट कर दिया। शिकायत में उल्लिखित घटनाक्रम के संबंध में क्या और कैसे हुआ, इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। यदि आचार संहिता के प्रावधानों के विपरीत दल का चुनाव चिह्न प्रदर्शित किया गया होना प्रमाणित होता है।

बलोच लिबरेशन आर्मी ने नुश्की शहर से सेना को खदेड़ा, मजीद ब्रिगेड के फिदायीन दंपति की मौत

एजेंसी

क्वेटा (बलोचिस्तान)। पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलोचिस्तान में सेना को विद्रोहियों से कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। बलोच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने दावा किया है कि नुश्की शहर से सेना को खदेड़ दिया है। शहर में अभी भी उसका नियंत्रण है। साथ ही पिछले दिनों के घमासान में बीएलए के मजीद ब्रिगेड के फिदायीन दंपति की मौत हो गई। इस बीच पाकिस्तान के रक्षामंत्री ने कहा कि बीएलए से सरकार कोई बातचीत नहीं करेगी। द बलोचिस्तान पोस्ट की मंगलवार को प्रसारित रिपोर्ट के अनुसार, नुश्की अभी भी बीएलए के नियंत्रण में है। जमीनी संचार सेवाएं बाधित हैं। लड़ाई में दर्जनों लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान की सेना के हवाई हमलों के बावजूद बलोच लड़ाके नुश्की शहर पर अपना नियंत्रण बनाए हुए हैं। खारान के पास बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने पाकिस्तान की सेना के दो जमीनी हमलों को विफल कर दिया। इसके बाद सेना को पीछे हटना पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेना ने दूसरे और तीसरे दिन दर्जनों ड्रोन हमले किए। बावजूद इसके सेना अभी तक नुश्की शहर पर दोबारा नियंत्रण हासिल करने में सक्षम नहीं हो पाई है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने शनिवार सुबह अन्य शहरों की तरह समन्वित अभियानों के माध्यम से नुश्की पर भी नियंत्रण कर लिया। इसके बाद सशस्त्र लड़ाको ने सरकारी इमारतों और पुलिस स्टेशनों के साथ-साथ पाकिस्तान के आईएसआई मुख्यालय और सेना के कई शिविरों पर हमला किया।पिछले तीन दिन से आईएसआई मुख्यालय में तैनात कई अधिकारी और कर्मचारी बीएलए के हमलों का शिकार हुए हैं। तीन दिन बीत जाने के बावजूद सेना अपने कर्मियों को बचाने और उन्हें सहायता प्रदान करने में विफल रही है। नुश्की शहर में नाकाबंदी के कारण अन्य शहरों के निवासी अपने रिश्तेदारों को लेकर चिंतित हैं। कैडेट कॉलेज में दर्जनों छात्र फंसे हुए हैं। इस बीच बीएलए के आधिकारिक चैनल हकाल पर मजीद ब्रिगेड में शामिल पति - पत्नी का फोटो और विवरण प्रसारित किया गया है। इस दंपति ने पाकिस्तान की सेना के शिविर पर हमले के दौरान जान गंवा दी। यास्मा बलूच उर्फ ??जरीना और वसीम बलोच उर्फ ??जरबर (पति-पत्नी) जमरान के रहने वाले थे। यास्मा बलोच का जन्म 14 फरवरी, 1997 को अल-अंदुर बुलाइदा में हुआ था और वह 2022 में मजीद ब्रिगेड में शामिल हुई थी। वसीम बलोच का जन्म 27 अप्रैल, 1992 को कलहादर ज़मरान में हुआ था। वह 2014 में बीएलए में शामिल हुए और 2022 में मस्जिद ब्रिगेड का हिस्सा बने। इस लड़ाई पर रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बलोचिस्तान में महिलाओं और बच्चों पर हमला करने वालों से कोई बातचीत नहीं होगी। आसिफ ने नेशनल असेंबली में कहा कि पंजाब में भी बड़ी संख्या में बलोच रहते हैं। बलोचिस्तान में मेडिकल कॉलेजों सहित बड़ी संख्या में शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थान हैं। बलोचिस्तान में तेल सहित विभिन्न सामानों की रोजाना तस्करी हो रही है। विद्रोही तेल की तस्करी से रोजाना चार अरब रुपये कमा रहे हैं। ईरान से 40 रुपये प्रति लीटर में तेल खरीदकर उसे कराची में 200 रुपये प्रति लीटर में बेच रहे हैं।

प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने पहली बार संसद के उच्च सदन को किया संबोधित

एजेंसी

काठमांडू। नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने संघीय संसद के अंतर्गत राष्ट्रीय सभा को पहली बार संबोधित किया है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी राजनीतिक यात्रा संयोग और परिस्थितियों का परिणाम है और यह संकेत दिया कि ऐसा क्षण दोबारा आना मुश्किल हो सकता है।

पिछले वर्ष सितंबर में हुए जेन-जी आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री बनीं कार्की ने स्पष्ट किया कि वह योजनाबद्ध तरीके से सत्ता में नहीं आईं। उन्होंने कहा कि संसद में खड़े होकर बोलना उनकी कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं थी, बल्कि यह समय और परिस्थितियों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि यह मेरे जीवन का ऐसा क्षण है, जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। न यह मेरी चाह थी, न ही मैंने इसे खोजा, बल्कि परिस्थितियां मुझे यहां ले आईं। आज जो अवसर मुझे मिला है, शायद वह जीवन में फिर दोहराना कठिन होगा। मैंने इसकी कभी उम्मीद भी नहीं की थी। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कहा कि शासकीय त्रुटियों और आचरणगत कमजोरियों के कारण ही जेन-जी विद्रोह हुआ। यह विद्रोह एक ऐसा आईना है, जिसमें हम अपनी ही शासकीय गलतियों और आचरणगत कमजोरियों को देख रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान संविधान द्वारा परिकल्पित संघीय गणतांत्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों और सुशासन सहित लोकतांत्रिक मूल्यों पर खरा न उतर पाने के कारण यह आंदोलन हुआ। युवा पीढ़ी सहित समूचे नेपाली समाज की आकांक्षाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि नागरिक राज्य के संसाधनों, साधनों और अवसरों तक समान पहुंच, रोजगार और गुणवत्तापूर्ण जीवन की अपेक्षा रखते हैं।

स्पेसएक्स और एक्सएआई का विलय, मस्क ने कहा-यह अध्याय नहीं, अभियान की अगली किताब

एजेंसी

वाशिंगटन। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और प्रसिद्ध टेक उद्यमी एलन मस्क की दो कंपनियों स्पेसएक्स और एक्सएआई का विलय हो गया। स्पेसएक्स ने घोषणा की कि उसने एक्सएआई को खरीद लिया है। इस विलय के बाद यह दुनिया की सबसे मूल्यवान प्राइवेट इकाई बन गई है। स्पेसएक्स की वेबसाइट पर एक बयान में मस्क ने कहा, यह सिर्फ अगला अध्याय नहीं, बल्कि स्पेसएक्स और एक्सएआई के अभियान की अगली किताब है।

सीएनएन की रिपोर्ट में इस विलय की जानकारी देते हुए कहा गया है कि इस विलय को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के तेजी से बढ़ते क्षेत्र में मुकाबला करने के लिए एक्सएआई को जरूरी नकद पूंजी और साथ ही अंतरिक्ष अन्वेषण

(स्पेस एक्सप्लोरेशन) के भविष्य में तकनीक (टेक्नोलॉजी) के महत्व के संकेत के तौर पर देखा जा सकता है।

यह कदम यह भी दिखाता है कि मस्क जैसी कंपनियों जैसे टेक दिग्गज एआई में ऊंची छलांग लगाने के लिए कितनी मशक्कत कर रहे हैं। मस्क ने लिखा, एआई में मौजूदा तरक्की बड़े जमीनी डेटा सेंटर पर निर्भर है। इसके लिए बहुत अधिक बिजली और कूलिंग की जरूरत होती है। इसलिए इस क्षेत्र को ऐसी जगह ले जाना है जहां बहुत अधिक बिजली और जगह हो। स्पेसएक्स ने फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन से 10 लाख सैटेलाइट का एक समूह ऑर्बिट में लॉन्च करने की इजाजत मांगी। अनुरोध में कहा गया है कि इसका मकसद सोलर-पावर्ड डेटा सेंटर का एक नेटवर्क देना है ताकि एआई की वजह से डेटा की बढ़ती डिमांड को पूरा किया जा सके। मस्क ने अनुमान जताया है कि दो से तीन साल में एआई कंप्यूट जेनरेट करने का सबसे सस्ता तरीका अंतरिक्ष में होगा।

इजराइल ने दक्षिण लेबनान में हिज्बुल्लाह ठिकानों पर किए हमले, पहले जारी की थी चेतावनी

एजेंसी

यरूशलम/बेरूत। इजराइल ने दक्षिण लेबनान में हिज्बुल्लाह से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई स्थानों पर हवाई हमले किए। हमलों से पहले इजराइली सेना ने दो गांवों 'कफर तिबनित' और 'ऐन काना' के लिए निकासी चेतावनी जारी की थी।

इजराइली सेना के अनुसार, ये कार्रवाई हिज्बुल्लाह के हथियार भंडारण स्थलों को नष्ट करने और उसकी दोबारा सक्रिय होने की कोशिशों को रोकने के उद्देश्य से की गई। सेना ने दावा किया कि कुछ ठिकाने रिहायशी इलाकों के बीच स्थित थे और हिज्बुल्लाह नागरिक ढांचे का उपयोग अपनी गतिविधियों के लिए कर रहा था।लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने भी दोनों

कस्बों में लक्षित इमारतों पर हमलों की पुष्टि की है। फिलहाल इन हमलों में हताहतों या नुकसान का विस्तृत ब्यौरा सामने नहीं आया है। क्षेत्र में पहले से जारी तनाव के बीच इन हमलों ने सीमा पार सुरक्षा हालात को और संवेदनशील बना दिया है। स्थानीय प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए है और प्रभावित इलाकों में स्थिति का आकलन किया जा रहा है।

कोस्टा रिका चुनाव में लौरा फ्रनांडीज़ ने किया जीत का दावा

एजेंसी

सैन होज़े। कोस्टा रिका की सत्तारूढ़ सॉवरेन पीपल पार्टी की उम्मीदवार लौरा फर्नांडीज़ ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि रविवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 48.3 प्रतिशत मत प्राप्त कर पहले ही दौर में चुनाव जीत लिया। सर्वोच्च निर्वाचन अधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक, 93.8 प्रतिशत मतदान केंद्रों की गिनती पूरी होने तक सुश्री फर्नांडीज़ ने नेशनल लिबरेशन पार्टी के उम्मीदवार अल्वारो रामोस को हराया, जिन्हें 33.4 प्रतिशत वोट मिले।

सिटीजन एजेंडा कोएलिशन की उम्मीदवार क्लाउडिया डोब्लेस को 4.9 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। कोस्टा रिका में पहले चरण में जीत के लिए 40 प्रतिशत से अधिक मत हासिल करना आवश्यक होता है। सुश्री फर्नांडीज़ ने जीत के बाद राजधानी सैन होज़े में समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि यह परिणाम देश के इतिहास में एक नये अध्याय की शुरुआत है, जिसे उन्होंने 'तीसरा गणराज्य' करार दिया। उन्होंने संवाद और सहमति पर आधारित शासन देने का संकल्प जताते हुए कहा कि जनता ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत करने तथा समृद्धि बढ़ाने के लिए परिवर्तन की निरंतरता के पक्ष में मतदान किया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति की घोषणा- भारत के साथ किया व्यापार समझौता, तत्काल टैरिफ कम होगा

एजेंसी

वॉशिंगटन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौता (ट्रेड डील) हो गया है। वह तत्काल एक-दूसरे के सामान पर टैरिफ कम करेंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रूस से तेल खरीदन बंद करने, अमेरिका और संभवतः, वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदने का वादा किया है। ट्रंप ने भारतीय नेता के साथ बातचीत के बाद ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भी समझौते के तहत अमेरिकी उत्पादों को अधिक मात्रा में खरीदने पर सहमत हुए हैं।

सीएनबीसी की रिपोर्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पूरी घोषणा का प्रसारण किया गया है। वह इस प्रकार है- आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। वह मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं और अपने देश के एक ताकतवर और सम्मानित नेता हैं। हमने कई बातों पर बात की, जिसमें ट्रेड और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करना शामिल है। वह रूसी तेल खरीद बंद करने और यूनाइटेड स्टेट्स और शायद वेनेजुएला से बहुत ज्यादा तेल खरीदने के लिए सहमत हुए। इससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने में मदद मिलेगी, जिसमें हर हफ्ते हजारों लोग मर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ दोस्ती और सम्मान के नाते और उनके अनुरोध पर तुरंत असर से हम यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के बीच एक ट्रेड डील पर सहमत हुए हैं, जिसके तहत यूनाइटेड स्टेट्स कम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा, इसे 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा। वे भी इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ अपने टैरिफ और नॉन-टैरिफ बैरियर को घटाकर शून्य कर देंगे। प्रधानमंत्री ने 46 लाख करोड़ रुपये (500 अरब डॉलर) से ज्यादा की अमेरिकी एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोयला और कई दूसरे प्रोडक्ट्स के अलावा, बहुत अधिक स्तर पर बाय अमेरिकन करने का भी वादा किया। भारत के साथ हमारे शानदार रिश्ते आगे और भी मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी और मैं दो ऐसे लोग हैं जो काम पूरा करते हैं, जो ज्यादातर लोगों के बारे में नहीं कहा जा सकता। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद! ट्रंप की घोषणा में कहा गया है कि फोन कॉल पर हुए समझौते बिना किसी देरी के लागू होंगे। सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन डील का लिखित स्वरूप अभी सामने नहीं आया है और यह साफ नहीं है कि इस पर हस्ताक्षर हुए हैं या नहीं। व्हाइट हाउस और यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के ऑफिस ने इस पर अधिक जानकारी के लिए किए गए अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। अमेरिका के कानूनी विशेषज्ञों और कुछ डेमोक्रेटिक सांसदों ने सवाल उठाया है कि क्या ट्रंप कांग्रेस की मंजूरी के बिना कोई भी बाध्यकारी व्यापार समझौता कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने दोबारा पद संभालने के बाद कई बार किया है। ट्रंप और उनके समर्थकों का तर्क है कि कांग्रेस ने ऐसे सौदे करने के लिए कार्यकारी शाखा को अधिकार दे दिया है।रोजर्स एंड ब्राउन कस्टम ब्रोकर्स की ऑपरेशंस डायरेक्टर लोरी मुलिंस ने बताया कि उनका समूह ट्रंप की सार्वजनिक व्यापार घोषणाओं पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं देगा। मुलिंस ने कहा, यह तभी आधिकारिक होता है जब फेडरल रजिस्टर नोटिस तारीखों, समय और लागू टैरिफ कोड के साथ पोस्ट किया जाता है।ट्रंप और मोदी प्रशासन के बीच व्यापार वार्ता पिछले साल कई मुद्दों पर अटक गई थी। इसकी वजह नई दिल्ली का रूसी तेल पर लगातार निर्भर होना शामिल था। अगस्त में ट्रंप ने तेल खरीद के जवाब में भारत पर 25 फीसद टैरिफ लगाया था। यह उस 25 फीसद पारस्परिक लेवी के अलावा था जो उसी महीने की शुरुआत में देश के अमेरिका जाने वाले सामानों पर लागू हुआ था।

page 1 and 8 Feb 4_page 1 Mar 25 final ds.qxd 2/4/2026 1:12 AM Page 2

अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक जल्दी तैयार होने वाला फल -पपीता

पपीता पोषक तत्वों से भरपूर अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक जल्दी तैयार होने वाला फल है पपीते का पके तथा कच्चे रूप में प्रयोग किया जाता है इसका आर्थिक महत्व ताजे फलों के अतिरिक्त पपेन के कारण भी है, जिसका प्रयोग बहुत से औद्योगिक कामों में होता है इसलिए पपीते की खेती की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह हमारे देश का पांचवा लोकप्रिय फल है देश के अधिकांश भागों में घर की बगिया से लेकर बागों तक पपीते की बागवानी का क्षेत्र निरन्तर बढ़ता जा रहा हैं

देश के विभिन्न राज्यों आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडू, बिहार, आसाम, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर तथा मिजोरम में इसकी खेती की जा रही है अतः इसके सफल उत्पादन के लिए वैज्ञानिक पद्धति या तकनीकों का उपयोग करके कृषक इसकी फसल से अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं इस लेख में कृषकों के लिए पपीते की वैज्ञानिक तकनीक से बागवानी कैसे करें की जानकारी का विस्तृत उल्लेख किया गया है

पपीते की खेती की सबसे अच्छी उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्रो में होती है लेकिन समशीतोष्ण क्षेत्रो में भी अच्छी पैदावार देता है शुष्क गर्म जलवायु में इसके फल अधिक मीठे होते है परन्तु अधिक नमी इसके फलो के गुणों को ख़राब कर देती है, और पैदावार भी प्रभावित होती है इसके उत्पादन के लिए तापक्रम 22 से 26 डिग्री सैंटीग्रेट के बिच और 10 डिग्री सेंटीग्रेट से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिक ठण्ड तथा पाला इसके लिए शत्रु के समान है

पपीता किसी भी प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी उपज जीवांश युक्त हलकी दोमट या दोमट मृदा जिसमे जल निकास कि व्यवस्था अच्छी हो, इसलिए इसके लिए दोमट हवादार काली उपजाऊ भूमि का चयन करना चाहिए और जिसका पीएच मान 6.5 से .5 के बिच होना चाहिए और पानी बिलकुल नहीं रुकना चाहिए, पपीते की खेती के लिए मध्य काली और जलोढ़ भूमि भी अच्छी होती है

पपीता में नियंत्रित परागण के अभाव और बीजय प्रर्वधन के कारण किस्में अस्थाई हैं तथा एक ही किस्म में विभिन्नता पाई जाती हैं अतः फूल आने से पहले नर और मादा पौधों का अनुमान लगाना कठिन है इनकी कुछ प्रचलित किस्में जो देश के विभिन्न भागों में उगाई जाती हैं और अधिक संख्या में मादा फूलों के पौधे मिलते हैं जिनमें मुख्य हैं, जैसे-

हनीड्यु या मधु बिन्दु, कुर्ग हनीड्यू, वांशिगटन, कोय- 1, कोय- 2, कोय- 3, फल उत्पादन तथा पपेन उत्पादन के लिए कोय- 5, कोय- 6, कोय- , एम एफ- 1 और पूसा मेजस्टी मुख्य हैं पपेन का अन्तराष्ट्रीय व्यापार में महत्व है इनमें पपेन अन्य किस्मों से अधिक निकलते हैं

उत्तरी भारत में तापक्रम का उतार-चढ़ाव काफी अधिक होता है इसलिए उभयलिंगी फूल वाली किस्में ठीक उत्पादन नहीं दे पाती हैं, जब कि कुर्ग हनीड्यू, दक्षिण भारत में अधिक पैदावार के लिए सफल सिद्ध हुई है

कोय- 1, पंजाब स्वीट, पूसा डेलिसियस, पूसा मेजस्टी, पूसा जाइन्ट, पूसा डुवार्फ, पूसा नन्हा, म्यूटेन्ट आदि किस्में, जिनमें मादा फूलों की संख्या अधिक होती हैं और उभयलिंगी हैं, उत्तरी भारत में काफी सफल हैं

हवाई की 'सोलो किस्म जो उभयलिंगी और मादा पौधे होते हैं, उत्तरी भारत में इसके फल छोटे और निम्न कोटि के होते हैं

पपीता के उत्पादन के लिए पौधशाला में पौधों को उगाना बहुत महत्व रखता है इसके लिए बीज की मात्रा एक हैक्टेयर में पपीता के लिए 500 ग्राम काफी होती है बीज पूर्ण पका हुआ, अच्छी तरह सूखा शीशे की बोतल या जार में रखा हो, जिसका मुंह ढका हो और 6 महीने से अधिक पुराना न हो, उपयुक्त है बोने से पहले बीज को केप्टान से उपचारित कर लेना चाहिए इसके लिए 3 ग्राम केप्टान एक किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए काफी है

बीज बोने के लिए क्यारी जो जमीन से उंची उटी हुई संकरी होनी चहिए, इसके अलावा बड़े गमले या लकड़ी के बक्सों का भी प्रयोग कर सकते हैं इन्हे तैयार करने के लिए पत्ती की खाद, बालु तथा सड़ी हुई गोबर की खाद बराबर भागों में मिलाकर मिश्रण तैयार कर लेते हैं जिस स्थान पर नर्सरी होती हैं, जमीन की अच्छी गुड़ाई-जुताई करके समस्त कंकड़ पत्थर तथा खरपतवार निकाल कर साफ कर देना चाहिए और जमीन को 2 प्रतिशत फोरमिलीन से उपचारित कर लेना चाहिए

वह स्थान जहां पर तेज धूप तथा अधिक छाया न आये चुनना चाहिए एक एकड़ के लिए 4056 मीटर जमीन में उगाये गये पौधे काफी होते हैं इसमें 2.5 X 10 X 0.5 आकार की क्यारी बनाकर उपर्युक्त मिश्रण अच्छी तरह मिला दें

और क्यारी को उपर से समतल कर दें इसके बाद मिश्रण की तह लगाकर 1/2 X 2 इंच गहराई पर 3 X 6 इंच के फासले पर पंक्ति बनाकर उपचारित बीज बो दें और फिर 1/2 X 2 इंच गोबर की खाद के मिश्रण से ढककर लकड़ी, से दबा दे ताकि बीज उपर न रह जाये

यदि गमलों या बक्सों का उगाने के लिए प्रयोग करें, तो इनमें भी इसी मिश्रण का प्रयोग करें बोई गई क्यारियों का सूखी घास या पुआल से ढक दें तथा सुबह व शाम हज्जारे द्वारा पानी देना आवश्यक है बोने के लगभग 15 से 20 दिन के भीतर बीज का जमाव हो जाता हैं जब इन पौधों में 4 से 5 पत्तियां निकल आयें तो छोटे गमले 6' आकार में मिश्रण भर कर लगा दें

जब पौधे खेत में प्रतिरोपण करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो प्रतिरोपण करने से पहले गमलों को धूप में एक दिन रखना चाहिए और खेत में सदैव पौधे संध्या के समय लगाकर उचित पानी देना चाहिए किसी भी हालत में पानी अधिक न हो जायें नहीं तो पौधों को तुरन्त सड़न और उकठा का रोग लग जायेगा उत्तरी भारत में नर्सरी में बीज मार्च, अप्रेल, जून और अगस्त में उगाने चाहिए

प्लास्टिक थैलियों में बीज उगाना- इसके लिए 200 गेज और 20 X 15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों की जरूरत होती है, जिनकों किसी कील से नीचे और साइड में छेद कर देते हैं तथा 1:1:1:1 पत्ती की खाद, रेत, गोबर और मिट्टी का मिश्रण बनाकर थैलियों में भर देते हैं प्रत्येक थैली में दो या तीन बीज बो देते हैं प्रतिरोपण करते समय थैली का नीचे का भाग फाड़ देना चाहिए

पौध लगाने से पहले खेत की अच्छी तरह तैयारी करके खेत को समतल कर लेना चाहिए, ताकि पानी न भर सकें फिर पपीता की सघन व्यावसायिक बागवानी के लिए 50 X 50 X 50 सेंटीमीटर आकार के गड्ढ़े 1.5 X 1.5 मीटर के फासले पर खोद लेने चाहिए ओर प्रत्येक गड्ढे में 30 ग्राम बी एच सी 10 प्रतिशत डस्ट मिलाकर उपचारित कर लेना चाहिए उंची बढ़ने वाली किस्मों के लिये 1.8 X 1.8 मीटर फासला रखते हैं जब पौधे 20 से 25 सेंटीमीटर हो जायें तो पहले से तैयार किये पौधों को 2 से 3 की संख्या में प्रत्येक गड्ढ़े में 10 सेंटीमीटर के फासले पर लगा देते हैं

पौधे लगाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं, कि गड्ढ़े का ढाल पौधे की तरफ हो, पौधे लगाने के बाद सिंचाई कर देनी चाहिए पपीता लगाने का उचित समय अप्रैल, अगस्त और सितम्बर है फूल आने के बाद केवल दस प्रतिशत नर पौधों को छोड़ कर सभी नर पौधों को निकाल देना चाहिए और उनकी जगह नये पौधे लगा दें बरसात के दिनों में पेड़ों के पास मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए, जिससे पानी तने से न लगे

पपीता जल्दी फल देना शुरू कर देता है, इसलिए इसे अधिक उपजाऊ भूमि की जरूरत है अतः अच्छी फसल के लिए 200 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फास्फोरस और 500 ग्राम पोटाश प्रति पौधा की आवश्यकता होती है इसके अतिरिक्त प्रति वर्ष पौधा 15 से 25 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद, 1 किलोग्राम हड्डी का चूरा तथा 1 किलोग्राम नीम की खली की जरूरत पड़ती है

खाद की यह मात्रा तीन बराबर मात्रा में मार्च से अप्रेल, जुलाई से अगस्त और अक्टूबर महीनों में देनी चाहिए दिसम्बर से जनवरी माह में उर्वरक नहीं डालना चाहिए, क्योंकि तापमान उत्तर भारत में इस समय काफी कम होता है और जाड़े में पौधों की वृद्धि रुक जाती है पपीता लगाने के 4 माह बाद से उर्वरक डालने की आवश्यकता होती है

पपीते के पौधे पानी के जमाव के प्रति संवेदनशील होते हैं अतः इन्हें ऐसी भूमि में लगाना चाहिए जहाँ पानी के निकास का उत्तम प्रबंध हो खास तौर पर जहाँ अधिक वर्षा होती है और भारी मिट्टी है, वहाँ का विशेष ध्यान रखना चाहिए पपीते के पौधों में समय-समय पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है पानी की कमी होने पर उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है यदि ठीक समय पर सिंचाई न की जाये तो पौधे की वृद्धि रुक जाती है जलवायु के अनुसार नये पौधों में 2 से 3 दिनों के अन्तर पर सिंचाई करनी चाहिए, जबकि एक साल पुराने पौधों में गर्मी में 6 से दिनों के अन्तराल पर तथा सर्दी में 10 से 15 दिनों के अन्तराल पर सिंचाई करनी चाहिए (जब वर्षा न हो)

पपीते के पौधे के पास पानी के जमाव होने पर पौधे में गलन की बिमारी लग जाती है और पौधा मर जाता है इसलिए पपीते के खेत में जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और पौधे की जड़ के पास 15 से 20 सेंटीमीटर ऊँची मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए, ताकि सिंचाई या वर्षा का पानी तने के सम्पर्क में न आये 60 से 80 प्रतिशत तक ज़मीन में उपलब्ध मृदा नमी सिंचाई के लिए उपयुक्त पायी गयी हैं यदि लम्बे समय तक पपीते के पौधे को पानी न मिले तो पौधे की वृद्धि एवं विकास रुक जाता है यह भी देखा गया है, कि पानी की कमी होने पर नर फूल अधिक निकलते हैं परन्तु यदि खेत में लम्बे समय तक अधिक नमी बनी हुई है, तो फल विकृत आकार के हो जाते हैं केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान में प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कि यदि पौधों को नाली से या पूरे खेत में पानी लगाने की तुलना में बेसिन विधि से सिंचाई करें, तो पानी कम लगता है तथा अधिक गुणवत्तायुक्त फल का उत्पादन होता है

पृष्ठ 1 का शेष

डोगरा समाज को पड़ोसी पहाड़ी-भाषी...

एसोसिएशन ने इस मुद्दे पर जम्मू के प्रमुख साहित्यिक और सांस्कृतिक संगठनों की चुप्पी पर निराशा व्यक्त की, जबकि लोकगीतों की सांस्कृतिक चिंताओं की हिफाजत में आवाज़ उठाने वाले हिमाचली कलाकारों की सराहना की।

वरिष्ठ पत्रकार और भाषा कार्यकर्ता रमन केसर ने कहा कि लोकगीतों के साथ छेड़छाड़ पश्चिमी पहाड़ी और डोगरी को अलग-अलग दिखाने

का प्रयास है, जिसका एसोसिएशन रचनात्मक और सशक्त ढंग से विरोध करेगी। इस अवसर पर रोहित महाजन, क्लस्टर हेड, जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले कलाकारों को ट्राफियां भेंट कर के सम्मानित किया।

कार्यक्रम के आयोजन में कैलाशपति शर्मा, सुदेश डोगरा, जगदीश शर्मा , कुलवीर सिंह , कर्नल सुनील शर्मा, नेहा शर्मा, सतपाल शर्मा और बोधराज ठाकुर, राज रैना जी का विशेष योगदान रहा।

डोगरा वेलफेयर एसोसिएशन पिछले चार वर्षों से लोहड़ी के अवसर पर लगातार यह आयोजन कर रही है। एसोसिएशन ने स्वयं को राजनीति से दूर रखा हुआ है और समाजी-सांस्कृतिक कार्यों में लगी हुई है

सरकार बडगाम जिले में ईंट भट्ठों और क्रशरों को गिराए जाने की जांच कराएग :सुरिंदर चौधरी

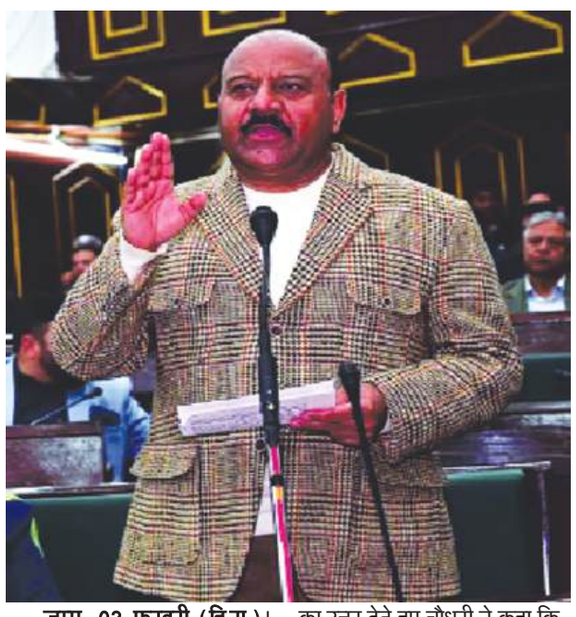

जम्मू, 03 फ़रवरी (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने मंगलवार को कहा कि सरकार बडगाम जिले में ईंट भट्ठों और क्रशरों को गिराए जाने की जांच कराएगी। विधायकों के इस आरोप के बाद यह निर्णय लिया गया कि पंजीकृत इकाइयों को निशाना बनाया गया जबकि अवैध इकाइयां चलती रहीं।

विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के विधायक डॉ. शफी अहमद वानी के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए चौधरी ने कहा कि बडगाम में 199 ईंट भट्ठे हैं। उन्होंने कहा, ''इनमें से 128 ईंट भट्ठों ने चालू वित्त वर्ष के दौरान ईंट बनाने के लिए इस्तेमाल की गई मिट्टी के लिए जिला खनिज अधिकारी के पास आवश्यक रॉयल्टी जमा कर दी है। यह मामला तब और बढ़ गया जब एनसी विधायक अली मोहम्मद डार ने आरोप लगाया कि उनके चदूरा निर्वाचन क्षेत्र में तीन ईंट भट्ठों को वैध पंजीकरण और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करने के बावजूद गिरा दिया गया। डार ने दावा किया कि विध्वंस प्रक्रिया के दौरान उनके साथ मारपीट की गई और बताया कि इलाके में कई अवैध भट्टे और क्रशर अभी भी अछूते हैं। एक समिति द्वारा जांच की मांग करते हुए, दार ने मंत्री से जवाब मांगा। उपमुख्यमंत्री ने विधायक के साथ कथित मारपीट की निंदा की और सदन को आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जाएगी।

हालांकि सदस्यों द्वारा आश्वासन से असंतुष्टि व्यक्त करने के बाद अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने हस्तक्षेप किया और सरकार से जवाब मांगा। चौधरी ने कहा कि आयुक्त सचिव जांच करेंगे और सदन को रिपोर्ट सौंपेंगे।'' उन्होंने कहा कि पंजीकरण प्रदान करने के लिए उपायुक्त प्राधिकारी जिम्मेदार है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भूविज्ञान और खनन विभाग को यह निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है कि इन इकाइयों द्वारा उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल वैध स्रोतों से प्राप्त और परिवहन किया जाए। विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 107 क्रशर यूनिट धारक और 44 हॉट-वेट मिक्स प्लांट आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकृत हैं। इन इकाइयों को अपनी वैध मात्रा को अद्यतन करना और सभी बिक्री और परिवहन ई-चालान और ई-परमिट के माध्यम से करना आवश्यक है।

केंद्रीय बजट 2026-27- प्रगतिशील और जन-केंद्रित बजट : पवन शर्मा

जम्मू, 03 फ़रवरी (हि.स.)। भाजपा के वरिष्ठ नेता और जम्मू-कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के राज्य सचिव पवन शर्मा ने माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 का हार्दिक स्वागत किया है। उन्होंने इसे दूरदर्शी, समावेशी और विकासोन्मुखी बजट बताया है, जो गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं और मध्यम वर्ग के हितों को सर्वोपरि रखते हुए विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूत करता है। पवन शर्मा ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के सशक्त और निर्णायक नेतृत्व को दर्शाता है जो आर्थिक स्थिरता, अवसंरचना विकास, रोजगार सृजन, सामाजिक कल्याण और आत्मनिर्भरता पर निरंतर ध्यान केंद्रित कर रही है।